लखनऊ

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

गुरुवार 12 फरवरी, 2026
वर्ष : 11 । अंक: 173
मूल्य : 1 रुपये
पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

जब क्रोध में हों, तो दस बार सोचकर बोलिए, जब ज्यादा क्रोधित अवस्था में हों, तो हजार बार सोचिए।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi | NIGHT 10° Low

लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख मिलेंगे:14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटी खुलेंगी, 400 करोड़ की स्कूटी बांटेंगे

नोएडा एयरपोर्ट पर पांच रनवे बनेंगे

बस अड्डों पर बनेंगे चार्जिंग प्वाइंट

ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर 50 करोड़ से चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे

>>> विधानसभा में 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट पेश

>>> यूपी में करीब 6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का दावा >>> यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, युवाओं को मिलेंगे Free टैबलेट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। वित्त मंत्री ने कहा कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27 प्रतिशत से नीचे लाया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

अपने घर, गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स-ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 01 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों/श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है।

> मैंने बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तरफ विकास हुआ है। साल 2024-2025 के लिए राज्य का GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.4 परसेंट ज्यादा है।'
>
> वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

400 करोड़ से छात्राओं को स्कूटी दी जाएंगी

परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22167 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा के लिए 6195 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। छात्राओं को 400 करोड़ से स्कूटी दी जाएंगी। शिक्षा व सामाजिक कल्याण के लिए भी बजट बढ़ाया गया है।

महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे

पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए अलग केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

शायरी पढ़कर वित्त मंत्री ने बांधी समां

यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है। दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। शायरी पढ़कर वित्त मंत्री ने बांधी समां।

न्याय विभाग के लिए 9845 करोड़ प्रस्तावित

न्याय विभाग की योजनाओं के लिए 9845 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें न्यायालय निर्माण से लेकर अन्य बिंदु शामिल हैं।

अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित

अटल आवासीय विद्यालयों में 10876 छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस योजना के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित हैं।

वित्त मंत्री ने पढ़ी शायरी

बड़ी मुश्किल से कोई सुबह हंसती है,,, गम की शाम चली आती है, महिला एवं बाल विकास के बारे में बताने से पहले वित्त मंत्री ने शायरी पढ़ी।

वन एवं पर्यावरण हमारे लिए गर्व का विषय

वन एवं पर्यावरण हमारे लिए गर्व का विषय है। कुकरैल में सफारी पार्क बनाया जाएगा। प्रदेश में रिकार्ड पौधे रोपे गए।

25 करोड़ से बनेंगे नवीन गोदाम

रासायनिक उर्वरकों के भंडारण के लिए 150 करोड़ की योजना प्रस्तावित है। नवीन गोदामों के लिए 25 करोड़ की योजना प्रस्तावित की जा रही है।

यूपी में 7497 गोशालाएं संचालित

बेसराहा पशुओं के संरक्षण के लिए 7497 गोशालाएं चल रही हैं। इनमें 12 लाख 38 हजार से अधिक गोवंश संरक्षित हैं।

44 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया

यूपी में करीब 29 लाख हेक्टेयर पर गन्ना उत्पादन किया गया। 44 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया।

किसान एग्री हब बन रहा

लखनऊ के गोमतीनगर में किसान एग्री हब का निर्माण चल रहा है। कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के कार्यक्रम चल रहे।

युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना आवश्यक

एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

युवाओं प्रशिक्षित किया जाएगा

ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी

पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल संवर्द्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी।

संक्षेप

डिजिटल अरेस्ट का खौफ: रिटायर्ड कैग अफसर को 18 दिन घर में कैद रखकर ठगे 2.13 करोड़; ऐसे बनाया शिकार

गुड़गांव। साइबर सिटी गुड़गांव में ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां साइबर अपराधियों ने एक सेवानिवृत्त कैग (ट्रत्र) अधिकारी और उनकी पत्नी को निशाना बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी मामले में फंसाने का डर दिखाया। शातिर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 18 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई यानी कुल 2.13 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ति की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-64सी के रहने वाले पीड़ति इंद्र कुमार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई। उनके पास व्हाट्सएप पर एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वालों ने खुद को सीबीआई, ईडी और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया। ठगों ने उनसे कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले से जुड़ा है और नरेश गोयल नामक व्यक्ति के केस में 20 लाख रुपये की संदिग्ध लेनदेन की बात कही गई। यहीं से डराने-धमकाने का खेल शुरू हुआ। ठगों का जाल इतना गहरा था कि उन्होंने पीड़ति दंपति को घर के अंदर ही 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया। आरोपियों ने स्काइप और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए उन पर लगातार निगरानी रखी। उन्हें डराने के लिए फर्जी लेटरहेड पर ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज दिखाए गए, जिनमें गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति जब्त करने के आदेश का जिक्र था। ठगों ने उन्हें किसी से भी बात करने या घर से बाहर निकलने तक से मना कर दिया था, जिससे दंपति बुरी तरह दहशत में आ गया।

राष्ट्रगीत के नियमों में बदलाव, अब खड़ा होना जरूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली। राष्ट्र गान 'जन गण मन' की तर्ज पर अब राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' को भी सरकारी कार्यक्रमों में बजाना और गाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए राष्ट्र गीत के गायन और वादन से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया है। मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी को जारी किए गए 10 पन्नों के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्र गान 'जन गण मन' दोनों को एक साथ गाया या बजाया जाना है, तो वरीयता 'वंदे मातरम' को दी जाएगी, यानी उसे पहले बजाया जाएगा। साथ ही, इसके सम्मान में श्रोताओं को अनिवार्य रूप से सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक, अब विभिन्न आधिकारिक अवसरों पर 'वंदे मातरम' का छह अंतरों वाला 3.10 मिनट की अवधि का संस्करण बजाया या गाया जाएगा। इन अवसरों में मुख्य रूप से तिरंगा फहराने के कार्यक्रम और सरकारी समारोह शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में आगमन पर, उनके भाषणों से पहले और देश के नाम संबोधन के पहले व बाद में भी इसे बजाना अनिवार्य होगा।

योगी ने हर व्यक्ति को बनाया 'दोगुना अमीर', महिला-युवा और किसानों के लिए खोला खजाना

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश कर दिया। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत के इस बढ़े बजट में सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और रोजगार निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा को 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य को छः प्रतिशत बजट आवंटित कर योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता स्वस्थ और शिक्षित समाज के निर्माण की है। सरकार ने यह भी बताया है कि उसके कार्यकाल में करीब 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और राज्य की प्रति व्यक्ति आय दो गुनी होकर

एक लाख 20 हजार से अधिक हो गई है। किसानों की आय भी दो गुनी हो चुकी है। इस तरह कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में यूपी वासियों को दो गुना अमीर बना दिया है।

महिलाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणा

महिलाएं योगी आदित्यनाथ की बड़ी समर्थक बनकर उभरी हैं। इसका कारण है कि योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। बजट के माध्यम से भी योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। बजट में अनुसूचित जातियों की गरीब बेटियों के विवाह के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग की गरीब बेटियों के विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मेधावी छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

किसान यूपी की शक्ति, खोला खजाना

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। प्रदेश की बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि कार्यों के माध्यम से ही अपना जीवन निर्वाह कर रही है। इसे देखते हुए सरकार ने बजट में किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। गन्ना किसानों को भुगतान में 3000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यूपी अनेक खाद्य फसलों के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। सरकार ने इसको बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भाजपा सरकार का यह आखिरी और विदाई बजट : अखिलेश यादव

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को उसका "आखिरी और विदाई बजट" बताते हुए कहा कि यह केवल आंकड़ों और प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में गरीबों, किसानों और युवाओं के हित में कोई ठोस प्रावधान नहीं है।राज्य मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में श्री यादव ने कहा कि बजट का आकार बढ़ने के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण क्यों नहीं हो सका। उन्होंने दावा किया कि सरकार पिछले बजट का 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाई है और जो जीएसडीपी के आंकड़े

प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए प्रदेश की जीएसडीपी 90 लाख करोड़ रुपये और विकास दर 30 प्रतिशत होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। कृषि, मध्यम उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है।निवेश के मुद्दे पर श्री यादव ने कहा कि सरकार 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू का दावा करती है, लेकिन जमीन पर निवेश नजर नहीं आता। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं है और नौजवान हताश हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का असर किसानों और लघु उद्योगों पर पड़ेगा, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है।किसानों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, आय दोगुनी करने और एमएसएमई के सशक्तिकरण पर कोई ठोस पहल नहीं दिखती। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई और आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है।

राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्सटीन फाइल्स का किया जिक्र, हंगामा

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को सवाल उठाया कि उद्योगपति अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं। उन्होंने संसद में आरोप लगाया कि एपस्टीन से संबंधित फाइलों में उनका नाम है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया और दावा किया कि पुरी जानते हैं कि अनिल अंबानी को एपस्टीन से किसने मिलवाया था।

राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यवसायी अनिल अंबानी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वह जेल में क्यों नहीं हैं? कारण यह है कि उनका नाम एपस्टीन फाइलों में है। मैं हरदीप पुरी से भी पूछना चाहता हूं कि उन्हें एपस्टीन से किसने मिलवाया था। मैं जानता हूं कि उन्हें किसने मिलवाया

था, और हरदीप पुरी भी जानते हैं कि उन्हें किसने मिलवाया था। केंद्रीय बजट पर अपने भाषण के बाद, कांग्रेस नेता ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए अपने आरोपों को दोहराया और दावा किया कि प्रधानमंत्री सीधे दबाव में हैं।

गांधी ने पत्रकारों से कहा कि मैंने कहा है कि मैं आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि करूंगा। न्याय विभाग के पास एपस्टीन मामलों से संबंधित फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं। अडानी के खिलाफ चल रहे एक मामले में समन जारी किए गए हैं। भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। सामान्य परिस्थितियों में कोई भी प्रधानमंत्री आंकड़ों, किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में ऐसा नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसा तभी करेगा जब उस पर कोई दबाव हो। 31 जनवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में जारी एपस्टीन फाइलों के कथित हिस्से के रूप में सामने आए एक ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2017 की इजराइल यात्रा के संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संदर्भ को एक दोषी अपराधी की बेतुकी बकवास करार दिया।

कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर से चैंबर में गाली-गलौच की... विपक्ष पर बरसे किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन यहां पर लगातार कुछ न कुछ हलचल बनी हुई है। विपक्षी सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में जाकर हंगामा करने के मामले पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कम से कम 20 से 25 कांग्रेस सांसद स्पीकर के चैंबर में घुस गए और उन्हें गालियां दीं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी को कुछ नहीं सिखा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में विपक्षी सांसदों के हंगामे पर निराशा जाहिर करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "कम से कम 20-25 कांग्रेस MP लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुस गए और उन्हें गालियां दीं। मैं भी वहीं पर मौजूद था।" उन्होंने आगे कहा, "स्पीकर बहुत नरम इंसान हैं, नहीं तो सख्त कार्रवाई होती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी अंदर मौजूद थे, और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे।"

स्पीकर इस घटना से बहुत दुखी: रिजिजू

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आगे कहा, "जैसा कि मैंने कहा, स्पीकर इस वाकये से बहुत दुखी हैं। मैंने स्पीकर से बात भी की है। वे (कांग्रेस सांसदों) स्पीकर के चैंबर में गए और उन्हें गालियां दीं, बुरी बातें कहीं। फिर स्पीकर ने एक रूलिंग दी, जिसका पालन नहीं हुआ और फिर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वह अपनी मर्जी से बोलेंगे, बिना किसी नियम के। जब तक चेयर से परमिशन नहीं मिलती, सदस्य सदन में नहीं बोल सकते। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी चेयर की परमिशन से ही बोलेंगे। हर कोई परमिशन लेकर ही बोलता है।" लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा, "मैं राहुल गांधी जी को कुछ नहीं सिखा सकता। मुझे समझ नहीं आता कि वह किस दुनिया में रहते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी उनके कामों को चलाती है?"

टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों का विरोध तेज, किया पुतला दहन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। टीईटी अनिवार्यता के मुद्दे पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का विरोध मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। स्थानीय तिकोनिया पार्क में शिक्षकों ने सरकार के कथित दोहरे मापदंड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस और शिक्षक नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई तथा धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। प्रदर्शन के दौरान नगर कोतवाल संदीप राय व पुलिस बल ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षकों ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जयंत चैधरी का पुतला जला दिया। बाद में पुलिस टीम ने पुतला बुझाकर अपने कब्जे में ले लिया। आक्रोशित शिक्षकों ने "टीईटी

वापस लो" और "मुंह पर इज्जत, पीठ पर वार। यह कैसा दोहरा व्यवहार" जैसे नारे लगाए। संघ के जिला प्रवक्ता निजाम खान ने बताया कि वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता को लेकर सरकार के साथ हुई वार्ता और संसद में दिए गए उत्तर में विरोधाभास है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति के समय शिक्षकों ने सभी मानदंड और अर्हताएं पूरी की थीं, तो 20-30 वर्ष बाद नई नीति लागू करना लाखों परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा करना है।प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सरकार के विरोध में सांकेतिक पुतला दहन किया गया। संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो यह लड़ाई जिले से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी और शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष होगा।जिला संयुक्त मंत्री प्रशांत पाण्डेय ने कहा कि टीईटी/सीटीईटी की अनिवार्यता शिक्षकों के साथ धोखा और अपमान है। सरकार जब तक विधेयक लाकर इसे समाप्त नहीं करती, तब तक शिक्षक अपने हक की लड़ाई जारी रखेंगे।जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-23 तथा एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में न्यूनतम योग्यता तय है। 25 वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को दोबारा परीक्षा के कटघरे में खड़ा करना न्यायसंगत नहीं है। इस अवसर पर जिला मंत्री डॉ. हृषिकेश भानु सिंह, निजाम खान जिला प्रवक्ता संयुक्त मंत्री प्रशांत पाण्डेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र नारायण मिश्र, जिला उपाध्यक्ष विनोद यादव, राम बहादुर मिश्रा, अंजनी कुमार शर्मा, अनिल यादव, लालचंद, सुरेश चंद्र पाल, डॉ. रीतेश सिंह, हेमंत यादव, राज कुमार चैधरी, अरविंद कुमार पाण्डेय, मजीद, किरण श्रीवास्तव, सुभाषिनी मिश्रा, शिवम राणे, डॉ. विक्रम सिंह, काशी त्रिपाठी, राकेश शुक्ला, मृदुल त्रिपाठी, नम्रता सिंह, रजनी गुप्ता, हिमांशु सिंह, चंद्र प्रकाश गुप्ता, हरिओम गुप्ता, संतोष कुमार सिंह, नीरज यादव, राज कुमार गुप्ता, डॉ. प्रदीप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

कमला नेहरू संस्थान में फायर सेफ्टी माक ड्रिल का आयोजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कमला नेहरू संस्थान के फरीदीपुर परिसर स्थित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में आज दिनांक 11/02/2026 को अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के द्वारा फायर सेफ्टी माक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन के बारे में फायर एन्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी भरत लाल तिवारी के द्वारा जानकारी प्रदान की गई। छात्र छात्राओं को विभिन्न आपदा प्रबंधन उपकरणों के प्रचालन बारे में भी जानकारी दी गई साथ ही डेमो करके भी दिखाया गया कि आज के वैज्ञानिक युग में सभी को आपदा प्रबंधन तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए द्य इंजीनियरिंग संकाय के निदेशक प्रो.(डा.) डी.एस. पुन्डीर ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया। संस्थान के डीन एकेडमिक रत्नेश सिंह ने बताया कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए बताई गई तकनीकें हम सभी के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। कार्यक्रम के अन्त में संचालन कर रहे मनोज भार्गव ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संस्थान के प्रबंधक एवं नगर विधायक विनोद सिंह ने जागरुकता के लिए इस आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। आज के कार्यक्रम में बी. टेक. तथा पालीटेक्निक के सभी छात्र छात्राओं सहित सभी विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक उपस्थित रहे।

प्रगतिशील किसान ने एसपी को भेंट किया 'काली आलू' व श्री अन्न का मिक्स आटा

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के प्रगतिशील किसान जमील अहमद ने पुलिस अधीक्षक का अभिनव तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने काली आलू की उन्नत प्रजाति कुफरी नीलकंठ तथा श्री अन्न (मोटे अनाज) से तैयार मिक्स आटा उपहार स्वरूप भेंट किया। किसान जमील अहमद ने बताया कि काली आलू की कुफरी नीलकंठ प्रजाति पोषक तत्वों से भरपूर है और बाजार में इसकी अच्छी मांग है। वहीं श्री अन्न से तैयार मिक्स आटा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और किसानों के लिए आय का नया स्रोत भी बन रहा है। एसपी मैडम ने किसान की नवाचारी सोच और कृषि के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जिले के प्रगतिशील किसान नई तकनीकों को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने भी जमील अहमद की पहल की सराहना की।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर 'फर्जी निस्तारण' का आरोप, राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

सुल्तानपुर। कुड़वार ब्लॉक के भण्डरा परशुरामपुर निवासी देव नाथ पाण्डेय ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायत के निस्तारण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रमुख सचिव, राजस्व उत्तर प्रदेश शासन को भेजे शिकायती प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनकी शिकायत संख्या 40017926002983 पर बिना समुचित जांच के ही झूठी आख्या लगाकर मामले को निस्तारित दिखा दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम सभा के बंजर गाटा संख्या 2321 और तालाब गाटा संख्या 2240 पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि जांच अधिकारी लेखपाल शैलेन्द्र श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक कुड़वार शिव प्रसाद कनौजिया तथा नायब तहसीलदार कुड़वार धर्मेंद्र यादव ने मौके पर निष्पक्ष जांच किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी।

साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारतीय सेना का सहयोगी बनेगा आइआइटी कानपुर, जल्द होगा एमओयू

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। साइबर और इलेक्ट्रानिक युद्धों के मोर्चे पर आइआइटी कानपुर अब भारतीय सेना का भरोसेमंद साथी बनेगा। इसके लिए संस्थान के इंजीनियर व विज्ञानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ), साइबर सुरक्षा, मानव रहित आटोनामस सिस्टम्स जैसी तकनीक का विकास भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर करेंगे।

भारतीय सेना और आइआइटी कानपुर के बीच इस सिलसिले में जल्द ही एक समझौता भी हो सकता है। मंगलवार को आइआइटी पहुंचे भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने आइआइटी निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल से मुलाकात के दौरान इसके संकेत दिए हैं।

उप सेनाध्यक्ष (वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ) लेफ्टिनेंट जनरल

पुष्पेंद्र सिंह ने निदेशक प्रो. अग्रवाल के साथ ही डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रो. तरुण गुप्ता और नोडल फैकल्टी प्रभारी प्रो. कांतेश बलानी के साथ एक अहम बैठक में रक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुसंधान व नवाचारों के बारे में जानकारी हासिल की है।

उप सेनाध्यक्ष ने भारतीय सेना में तकनीक आधारित आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया। आइआइटी निदेशक ने बताया कि भविष्य में सीमा पर साइबर और इलेक्ट्रानिक युद्ध होंगे।

इसके लिए सेना को तकनीक से मजबूत किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। एआइ, आटोनामस सिस्टम्स जैसी नई तकनीकें सैन्य संचालन के तरीकों में बदलाव के लिए तैयार हैं। उप सेनाध्यक्ष आइआइटी के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के नवाचारों में खासी दिलचस्पी दिखाई। प्रो. अभिषेक ने उन्हें मानवरहित हेलीकाप्टर, वीटीओएल और प्रो. सुब्रमण्यम सडरेला ने यूएवी (अनमैंड एयरव्हीकल) अनुसंधानों के बारे में बताया। आपदा, युद्ध और सर्विलांस में कारगर ड्रोन के माडलों और आत्मघाती ड्रोन की बारीकियां भी बताई। सी3आइ हब के विशेषज्ञ मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी डा. रस द्विवेदी व मुख्य रणनीति अधिकारी डा. आनंद हांडा ने साइबर सुरक्षा प्रणालियों के बारे में बताया।

बता दें कि सी3आइ हब आइआइटी में स्थित एक टेक्नोलाजी इनोवेशन हब है। यह साइबर-फिजिकल सिस्टम (जैसे पावर ग्रिड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर) की सुरक्षा के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करता है।

कानपुर में दो साल पहले जिस कुंडे से पति ने लगाया था फंदा, उसी से लटककर पत्नी ने दी जान

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

कानपुर। गोविंद नगर में जिस कुंडे से दो साल पहले पति ने फंदा लगाकर जान दी थी, सोमवार को महिला ने भी उसी से लटक कर खुदकुशी कर ली। स्वजन के मुताबिक पति की मौत के बाद वह अवसाद में थीं और उनका इलाज भी चल रहा था।

दबौली निवासी स्नेहलता वर्मा दूसरी मंजिल पर रहती हैं। भूतल पर छोटा बेटा विजय राज, पत्नी दीपाली व बेटी लाडो के साथ रहता है। वहीं पहली मंजिल पर 37 वर्षीय बड़ी बहू अंजलि, बेटी अद्रिका और बेटे रक्षित के साथ रहती थीं। विजय ने बताया कि मंगलवार को घर पर उनकी पत्नी दीपाली और भाभी अंजलि ही थीं।

दोपहर में दीपाली कपड़े फैलाने छत पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। इस पर अनहोनी की आशंका जताकर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी पड़ोस की छत से होकर अंदर पहुंचे तो कमरे में दुपट्टे के सहारे कुंडे से शव लटका रहा था।

विजय के अनुसार भाभी के पास ई-आटो थी, जिसके चालक का पांच दिन पहले एक्सीटेंड हो गया था। इसको लेकर भी वह परेशान थीं। कार्यवाहक गोविंद नगर थानाप्रभारी अभय सिंह ने बताया कि पति के आत्महत्या करने के बाद से महिला अवसाद में थीं।

जेठानी के गहने चुराकर घरवालों से बोली– भिखारियों ने किया ये सब... कैसे पकड़ा गया देवरानी का चोरी कांड

आर्यावर्त संवाददाता

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां देवरानी ने अपनी ही जेठानी की अलमारी से करीब 14 तोले सोने के जेवर चोरी कर लिए और आरोप भिक्षा मांगने आए भिखारियों पर लगा दिया। उसने कहानी गढ़ी कि चाकू की नोक पर लूटपाट की गई, लेकिन पुलिस की जांच में पूरा मामला झूठा निकला। पुलिस ने आरोपी देवरानी शिवानी, उसकी मां संजो देवी और भाई पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

मामला हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के मंडोरा जट गांव का है। 7 फरवरी को गांव निवासी योगेंद्र सिंह ने थाने में सूचना दी कि सुबह करीब नौ बजे उनकी पुत्रवधु शिवानी घर में अकेली थी। इसी दौरान भीख मांगने के बहाने एक पुरुष और एक महिला घर में घुस आए और चाकू की नोक पर लूटपाट की। शिवानी ने बताया कि आरोपियों ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया

और दूसरी मंजिल पर स्थित जेठ-जेठानी के कमरे से जेवर लेकर फरार हो गए।

चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी अभिषेक झा, एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार और सीओ चांदपुर देश दीपक सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घर का बारीकी से निरीक्षण किया और शिवानी से पूछताछ की। शिवानी ने बताया कि उसके ससुर खेत पर गए थे, पति अमित अपनी बहन को परीक्षा दिलाने मुरादाबाद गया था, जबकि जेठ सुमित सेना में है और जेठानी आरती उसके साथ रहती है।

जांच के दौरान पुलिस को कई बातें संदिग्ध लगीं। पूरे घर में सिर्फ जेठ-जेठानी के कमरे की अलमारी का ताला टूटा मिला, जबकि शिवानी के कमरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। शिवानी की गर्दन पर चाकू का घाव भी बेहद मामूली था। आसपास के लोगों ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को घर में आते-जाते नहीं देखा। मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी किसी के आने या जाने का कोई फुटेज नहीं मिला।

कैसे खुली पोल?

सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शिवानी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। चार से सात फरवरी के बीच उसने अपने भाई पंकज और मां संजो देवी से करीब 20 बार लंबी बातचीत की थी। सख्ती से पूछताछ करने पर शिवानी ने कबूल कर लिया कि उसने 4 फरवरी को ही जेठानी की अलमारी का ताला तोड़कर जेवर निकाल लिए थे और अपने भाई को दे दिए थे।

पंकज और संजो देवी ने जेवरों को पॉलिथीन में भरकर गन्ने के खेत में दबा दिया था। शिवानी ने बताया कि उसका भाई अविवाहित है और उसकी शादी के लिए जेवर जुटाने के मकसद से यह साजिश रची गई थी। पुलिस ने गन्ने के खेत से सभी 14 तोले सोने के जेवर बरामद कर लिए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

पॉड कास्टिंग लैब का हुआ शुभारंभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले में प्रथम पॉड कास्टिंग लैब का उद्घाटन राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र सिंह वत्स द्वारा फीता काटकर किया गया। मुख्य अतिथि को श्री कृष्ण पांडेय द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। नगर क्षेत्र के सौरमऊ स्थित नेशन व्यू 24 चैनल के पॉड कास्टिंग लैब के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक धरती पर संवाद की नई संस्कृति का शुभारंभ हो रहा है। यह केवल तकनीकी का उद्घाटन नहीं बल्कि विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जागरूक नागरिकता के सशक्त मंच की स्थापना है। जिले के इस प्रथम पॉडकास्ट चैनल से युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को ज्ञान विचार मंच मिलेगा। किसानों ,मजदूरों व सामाजिक व्यक्तियों को अपनी बात रखने का शसक्त माध्यम होगा। उन्होंने जिले की यह पहल अन्य जिलों के लिए प्रेरणा बनेगी और यह केंद्र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में कमला विद्या मंदिर की नन्हीं बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन आकाशवाणी लखनऊ की एंकर शालिनी सिंह द्वारा किया गया और लोक गायक दीन बंधु सिंह ने भी प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस मौके पर परियोजना निदेशक अशोक सिंह,भाजपा नेता प्रदीप मिश्रा सरकार, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह, ओम प्रकाश पांडेय बजरंगी, पूर्व मंत्री डॉ शैलेन्द्र त्रिपाठी, सपा नेता अशोक सिंह बिसेन, सलमान खान, कांग्रेस नेता राजेश तिवारी, अरविंद चतुर्वेदी, किसान यूनियन गिरीश पांडेय सहित पत्रकार अंकित राय, श्याम चंद्र श्रीवास्तव, अनिल द्विवेदी, योगेश यादव, राजदेव शुक्ला, पवन मिश्र, पंकज पांडेय, दीपक सिंह, इम्तियाज रिजवी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे।

मर चुकी पत्नी के 'भूत' ने भेजा ओ.टी.पी? मोबाइल देख पति के छूटे पसीने, पहुंचा थाने, फिर खुला अजीबोगरीब राज

आर्यावर्त संवाददाता

बस्ती। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला की हत्या की FIR उसी के पति ने दर्ज करवाई थी। पुलिस तलाश कर रही थी कि आखिर महिला है तो है कहां। अगर उसकी हत्या भी हुई है तो कम से कम उसका कुछ सुराग तो हाथ लगे। मगर दो साल तक महिला का कुछ भी नहीं पता लगा। फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, जिसे जानकर पुलिस से लेकर महिला के पति तक, हर कोई हैरान रह गया।

वो महिला न केवल जिंदा मिली। बल्कि दूसरे राज्य में अपना नया घर बसा चुकी थी। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाव गांव का है। यहां रहने वाली प्रियंका नामक युवती की शादी 14 मई 2017 को संदीप संग हुई थी। शादी के बाद सात साल

तक वैवाहिक जीवन अच्छा रहा। दोनों को एक प्यारा सा बेटा भी हुआ। मगर फिर पति-पत्नी में अक्सर लड़ाई-झगड़े होने लगे।

जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2024 को विवाद इतना बढ़ा कि प्रियंका घर से गहने लेकर मायके चली गई। फिर वहां से अपने बेटे को लेकर आत्महत्या करने के इरादे से अयोध्या पहुंच गई। सरयू नदी के किनारे जब वह जान देने वाली थी, तभी राजस्थान से दर्शन करने आए मंगलचंद्र ने उसे देख लिया। उसने प्रियंका की जान बचा ली। इसके बाद प्रियंका ने मरने का इरादा त्याग दिया। फिर मंगलचंद्र के साथ राजस्थान चली गई। वहां दोनों पति-पत्नी की तरह लिव-इन में रहने लगे।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

इधर बस्ती में पत्नी और बच्चे के अचानक लापता होने से पति संदीप टूट गया। वो उन्हें ढूंढता रहा, मगर वो दोनों नहीं मिले। फिर उसे शक हुआ कि उसके ससुराल वालों ने ही जेवर के लालच में प्रियंका और बच्चे की हत्या कर लाश नदी में फेंक दी होगी। संदीप ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की, तो संदीप कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर 4 नवंबर 2024 को प्रियंका के माता-पिता, चचेरी बहन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया।

एक OTP ने पलट दी पूरी बाजी

दो साल बीत गए। प्रियंका राजस्थान में अपनी पहचान बदलना चाहती थी। वो एक आधार सेंटर पर अपना फोटो और पता अपडेट करवाने पहुंची। जैसे ही उसने पुराना आधार नंबर डाला, लिंक मोबाइल नंबर (जो उसके पहले पति संदीप के पास था) पर एक OTP गया। संदीप ने जब ओटीपी देखा तो उसे माजरा समझते देर न लगी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

राजस्थान से बरामद किया प्रियंका को

पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली, राजस्थान पहुंचकर प्रियंका को बरामद कर लिया। जब प्रियंका को बस्ती लाया गया, तो वहां का दृश्य देखने लायक था। संदीप ने जैसे ही अपनी पत्नी और बेटे को देखा तो वो भावुक हो गया। संदीप को प्रियंका पर गुस्सा भी था। उसने कहा- मैं प्रियंका को साथ नहीं रखना चाहता। बस अपने बेटे को साथ ले जाना चाहता हूं। मगर बेटे ने संदीप के साथ न सिर्फ जाने से मना कर दिया, बल्कि उसे पापा मानने से भी इनकार कर दिया।

बच्चे की कस्टडी के लिए कार्रवाई

एएसपी श्यामकांत ने बताया- हत्या की FIR कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी। महिला के जिंदा मिलने के बाद अब कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए गए हैं। बच्चे की कस्टडी को लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई जाएगी।

मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को दो दिवसीय मंडलीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में अयोध्या मंडल के पांच जिलों के विजेता खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी मायाराम और विशिष्ट अतिथि कौतुभ कुमार सिंह मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता 11 और 12 फरवरी को आयोजित की जा रही है। इसमें अयोध्या मंडल के अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अमेठी जनपदों से आए प्रथम स्थान प्राप्त खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला क्रीड़ाधिकारी राजेश सोनकर भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी और 100 मीटर दौड़ जैसी प्रमुख खेल स्पर्धाएं शामिल हैं। इन आयोजनों के माध्यम से बच्चों को अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने मीडिया को प्रतियोगिता की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। मायाराम और अपर निदेशक बेसिक कौतुभ कुमार सिंह ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस आयोजन को सफल बनाने में जिले और ब्लॉक स्तर के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षक साथियों और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान बीएसए उपेंद्र गुप्ता ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। खेलकूद से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और स्थिरता भी आती है। गुप्ता ने आज की डिजिटल जीवनशैली का जिक्र करते हुए कहा कि बच्चों के लिए मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर मैदान पर पसीना बहाना बेहद जरूरी है। यह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होगा।

विकसित भारत की संकल्पना को समर्पित है यूपी का बजट 2026–27: केशव प्रसाद मौर्य

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट प्रावधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पना को समर्पित और जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में ठोस कदम है, जिसमें नारीशक्ति, किसान, युवा और समाज के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट से प्रदेश का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित होगा तथा उत्तर प्रदेश खुशहाली के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्तव्य आधारित ढांचे को अंगीकृत करते हुए प्रदेश में निरंतर और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण और जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने के लिए व्यापक बजटीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों, युवाओं, श्रमिकों, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सड़क एवं सेतु, सिंचाई, ऊर्जा, नगर विकास, पर्यटन, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन, मत्स्य, सहकारिता, शिक्षा, कौशल विकास, खेल, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, परिवहन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं।ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गांवों के समग्र विकास, रोजगार सृजन और आवास सुनिश्चित करने के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रस्तावित प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए 5,544 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 4,580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं को विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए 6,102 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 से 2025–26 तक 36 लाख 56 हजार आवास के लक्ष्य के सापेक्ष 36 लाख 37 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 4 लाख 61 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 3 लाख 67 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 822 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण संपर्क मार्गों में सुधार होगा।खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपये तथा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने और रोजगार सृजन में सहायक होगा।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार, बड़े पैमाने पर निवेश, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

ऐतिहासिक बजट से यूपी बनेगा विकसित और आत्मनिर्भर : पंकज चौधरी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे जनआकांक्षाओं को समर्पित, जनकल्याण, सुशासन और समृद्धि के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट बताया है।उन्होंने कहा कि यह बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता का परिणाम है। राज्य सरकार द्वारा 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक है। इससे विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को और अधिक गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विकास और विश्वास का जो मॉडल स्थापित किया है, यह बजट उसी का सशक्त प्रतिबिंब है।श्री चौधरी ने कहा कि बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। मातृशक्ति की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप और रोजगार से जोड़ने वाली व्यापक योजनाएं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगी।उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों से प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन होगा। कृषि एवं किसान कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सिंचाई, भंडारण, आधुनिक तकनीक और कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। गन्ना मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि को उन्होंने किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताया।प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश में विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे निर्णय मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा।श्री पंकज चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाएगा।

परिवहन विभाग को मिला मजबूती का बजट, सार्वजनिक परिवहन होगा सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण–अनुकूल : दयाशंकर सिंह

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रदेश बजट में परिवहन विभाग के लिए किए गए प्रावधानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा।परिवहन मंत्री ने बताया कि बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण के लिए ई-बसों की खरीद हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जबकि बस अड्डों के निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा, यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और परिवहन तंत्र अधिक सक्षम व सुव्यवस्थित बनेगा।दयाशंकर सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा विजन योजना" के अंतर्गत दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा दुर्घटना के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह प्रावधान सड़क सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।उन्होंने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे हरित ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ और सतत परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।परिवहन मंत्री ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को आधुनिक परिवहन अवसंरचना से सुसज्जित करने, सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस आधार प्रदान करेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश की जनता को योजनाओं का शीघ्र लाभ मिल सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल परिवहन सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सुलभ और तकनीक-सक्षम बनाकर आमजन के जीवन को सुगम बनाना है।

योगी सरकार का बजट प्रदेश को देगा नई रफ्तार: अमर नाथ मिश्र

लखनऊ। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमर नाथ मिश्र ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को विकास की नई रफ्तार देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदृष्टि और योजनाबद्ध कार्यशैली का सकारात्मक प्रभाव अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।अमर नाथ मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश की तीसरी सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य तय किया गया है, वह केवल घोषणा नहीं बल्कि ठोस रणनीति और योजनाओं के माध्यम से साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापार, उद्योग, बुनियादी ढांचे और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बजट में किए गए प्रावधान प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगे।उन्होंने आगे कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक कॉरिडोर, एमएसएमई को प्रोत्साहन और डिजिटल व्यवस्थाओं के विस्तार ने व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती दी है।

यूपी बजट 2026–27 लोकलुभावन अधिक, वास्तविक उत्थान कम : मायावती

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के बजट को लोकलुभावन बताते हुए कहा कि यह जनता के वास्तविक उत्थान और सर्वसमाज के संतुलित विकास के बजाय अधिकतर घोषणाओं तक सीमित प्रतीत होता है।उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और आश्वासनों को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वे केवल कागजी न रह जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि पिछले वर्ष के बजट के जमीनी क्रियान्वयन का ठोस और विश्वसनीय आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता, तो बजट भाषण अधिक भरोसेमंद बनता। उनके अनुसार वर्तमान बजट अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला अधिक प्रतीत होता है, जबकि प्रदेश की जनता को स्थायी आमदनी वाले रोजगार की आवश्यकता है।मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर समुचित ध्यान देने तथा बैकलॉग भर्तियों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट वर्ग या क्षेत्र विशेष का हितकारी न होकर करोड़ों गरीबों और किसानों के जीवन सुधार का माध्यम होना चाहिए।उन्होंने यह भी कहा कि यदि भाजपा सरकार बीएसपी की चारों सरकारों की तरह 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की संवैधानिक भावना के अनुरूप कार्य करे, तो यह जनहित में बेहतर होगा।इसके अतिरिक्त, मायावती ने बताया कि पार्टी की गतिविधियों के क्रम में आज राजस्थान सहित तीन राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की तैयारी और जनाधार बढ़ाने की रणनीति की समीक्षा की गई। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन को मजबूत कर सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें, ताकि संविधान प्रदत्त अधिकारों और आरक्षण का लाभ समाज के वंचित वर्गों को प्रभावी रूप से मिल सके।

'महोबा सूर्य महोत्सव' से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से 'महोबा सूर्य महोत्सव' का शुभारंभ 11 फरवरी से हो गया है। 17 फरवरी तक चलने वाला यह सात दिवसीय महोत्सव सूर्य के सात रंगों की अवधारणा पर आधारित है, जो ऊर्जा, बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वीरता का प्रतीक है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य महोबा स्थित प्राचीन रैहेलिया सूर्य मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।महोत्सव का शुभारंभ रैहेलिया सागर तट स्थित सूर्य मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और भगवान सूर्य की आरती के साथ हुआ। इसके बाद सूर्य मंदिर से मोदी ग्राउंड तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।महोत्सव का प्रमुख आकर्षण पहली बार आयोजित तारामंडल प्रदर्शनी है, जो 11 से 14 फरवरी तक चलेगी। इसमें दूरबीन से ग्रह-दर्शन, वर्चुअल रियलिटी अनुभव और विशेष सोलर फिल्टर से सूर्य दर्शन की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।मोदी ग्राउंड में 11 से 17 फरवरी तक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

घर से 500 मीटर दूर कटी मिलीं सहेलियां, बचपन से एक साथ ही रहती थीं ; एक की 6 महीने पहले हुई थी शादी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रहीमाबाद के दिलावरनगर रेलवे स्टेशन के बीच बेलवा फाटक के पास बुधवार सुबह दो सहेलियों नीतू (23) और शशि (20) ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चल सका है। नीतू बुधवार सुबह ही मायके आई थीं। दोनों बचपन से साथ रहती थीं। इस घटना से गांव में कई तरह की चर्चा है।

मनकौटी के राजाखेड़ा गांव निवासी नीतू का विवाह छह माह पूर्व उन्नाव के औरास धनैया खेड़ा निवासी ईशू से हुआ था। बुधवार सुबह करीब 10 बजे नीतू देवर के साथ गांव आई थीं। पिता बुद्धा ने बताया कि नीतू सहेली शशि से मिलने गई थी। दोनों घर से लगभग 400 मीटर दूर रेलवे ट्रैक पर पहुंचीं और ट्रेन के सामने कूद गईं। ट्रेन चालक की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। छानबीन में रेलवे लाइन से थोड़ी दूरी पर स्थित बाग में उनकी चप्पलें और स्टॉल मिले।

एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि दोनों की बचपन से गहरी दोस्ती थीं और अक्सर साथ रहती थीं। शादी के बाद भी नीतू अक्सर मायके में ही रहती थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। नीतू के देवर ने बताया कि नीतू ने पिता से मिलने की बात कही। इस पर वह उन्हें लेकर आए थे। नीतू के पति ईशू दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं।

गांव में तरह-तरह की चर्चा: ग्रामीणों ने दोनों को सुबह रेलवे लाइन किनारे हाथ में हाथ डाले जाते देखा था। एक घंटे बाद उनकी मौत की सूचना मिली। गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शशि, नीतू के देवर से शादी करना चाहती थी लेकिन शशि के पिता इसके लिए राजी नहीं थे। वहीं, कुछ का मानना है कि दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं होना चाहती थीं।

नीतू की शादी के बाद से शशि गुमसुम रहने लगी थी। शशि की शादी एक वर्ष पूर्व तय हुई थी लेकिन गोद भराई के बाद टूट गई थी। शशि के परिवार में अशर्फी लाल, बहन पूना, भाई राजकुमार, विनोद, मनीष, विकास और अवधेश हैं। वहीं, नीतू के परिवार में बुद्धा, भाई नरेश, बहनें अनीता और मीरा हैं। शशि ने हाईस्कूल और नीतू ने इंटर तक की पढ़ाई की थी।

संक्षेप

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता–2026 का भव्य आयोजन 13 फरवरी से

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग द्वारा द्वितीय बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता–2026 का आयोजन भव्य एवं गरिमामय स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की 36 टीमों ने पंजीकरण कराया है, जो इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाता है।यह प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण एवं विधि विभागाध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा के निर्देशन में आयोजित की जा रही है। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का उद्घाटन 13 फरवरी को किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।उद्घाटन दिवस पर ड्रा ऑफ लॉट्स, रिसर्वर टेस्ट एवं वर्चुअल उद्घाटन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण 14 फरवरी से शुरू होंगे, जिनमें प्रतिभागी टीमें अपनी वकालत कौशल, शोध क्षमता और न्यायालयीन प्रस्तुतीकरण का प्रदर्शन करेंगी।राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता विधि छात्रों को व्यावहारिक अधिवक्ता कौशल विकसित करने, शोध दक्षता सुदृढ़ करने और न्यायालयीन कार्यप्रणाली की गहन समझ प्राप्त करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगी।

शहर के शौचालयों की स्वच्छता पर सख्त निर्देश, नगर आयुक्त ने बुलाई समीक्षा बैठक

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा शहर के सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता एवं संचालन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त आईएएस गौरव कुमार ने की। इसमें शौचालयों का संचालन कर रही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की टूट-फूट या अव्यवस्था की स्थिति में तत्काल मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि शौचालयों का रखरखाव निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।उन्होंने अधिकारियों और संबंधित संस्थाओं को निर्देशित किया कि वे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करें तथा शौचालयों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं। नगर आयुक्त ने कहा कि नागरिकों को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिकता है।बैठक में अपर नगर आयुक्त अरविंद राव, उप नगर आयुक्त सुश्री रश्मि भारती, पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान, सभी जोनल अधिकारी एवं जोनल सेनेटरी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एनएच–30 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से किशोर की मौत, एक घायल

लखनऊ। थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे–30 स्थित अर्जुनपुर कट के पास बुधवार को सड़क दुर्घटना में एक किशोर की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।पुलिस के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2026 को लगभग 15:50 बजे दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक सुमित कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दो किशोर स्कूटी संख्या UP32MT4668 से अर्जुनपुर चौराहे से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।दुर्घटना में अबूसाद (14 वर्ष), पुत्र रशीद, निवासी भैंसामऊ गांव, थाना बीकेटी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मुस्तफा (16 वर्ष), पुत्र वसीम, निवासी अर्जुनपुर, थाना इटौंजा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, बीकेटी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर परिजनों की उपस्थिति में पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आशियाना में बंधन बैंक की नई शाखा का शुभारंभ, विवेकानंद पॉलीक्लिनिक को उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भेंट

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बंधन बैंक ने बुधवार को आशियाना, लखनऊ में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। शाखा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं सीबीओ राजिंदर कुमार बब्बर तथा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम एवं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ के सचिव स्वामी मुक्तिनाथानंद की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

नई शाखा के उद्घाटन के साथ ही बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के अंतर्गत विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एंड इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ को एक उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी दान की। एम्बुलेंस की चाबी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजिंदर कुमार बब्बर ने स्वामी मुक्तिनाथानंद को सौंपते हुए आपात चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण बताया।बंधन बैंक ने कहा कि शाखा नेटवर्क के निरंतर विस्तार से स्पष्ट है कि बैंक विविधीकरण और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर जोर दे रहा है। आशियाना में नई शाखा खुलने से स्थानीय ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा और उन्हें नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान उपलब्ध होंगे। इस विस्तार के साथ बैंक उत्तर प्रदेश में 560 शाखाओं के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से 32 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है, जबकि देशभर में इसकी 6,490 से अधिक शाखाएं संचालित हैं।कार्यकारी निदेशक एवं सीबीओ राजिंदर कुमार बब्बर ने कहा कि बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार कर रहा है ताकि उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि आशियाना में नई शाखा की शुरुआत बैंक की इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएसआर पहलों के माध्यम से बैंक आपात चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न समुदायों को सेवा देने वाले अस्पतालों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जरूरत के समय लोगों को समय पर उपचार मिल सके।बंधन बैंक ने अपनी 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभर में कुल 18 उन्नत लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दान की हैं। यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये एम्बुलेंस दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, कटक, वडोदरा, जयपुर, मथुरा, जालंधर, अहमदनगर, पूर्व मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, सूरत और सिकंदराबाद सहित विभिन्न शहरों के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों को प्रदान की गई हैं।बंधन बैंक का कहना है कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और अस्पतालों को सहयोग देने के माध्यम से वह एक अधिक सशक्त, स्वस्थ और सक्षम समाज के निर्माण में योगदान देने का प्रयास कर रहा है।

मछली मंडी के सामने भीषण सड़क हादसा, इको वैन और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर में युवक की मौत, तीन घायल

लखनऊ। 10/11 फरवरी 2026 की रात्रि थाना क्षेत्र में मछली मंडी के सामने इको वैन और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया।प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि में थाना स्थानीय पर सूचना मिली कि मछली मंडी के सामने एक इको वैन और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच टक्कर हो गई है। सूचना पर पुलिस बल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर जांच में सामने आया कि इको वैन संख्या UP77Q1222, जो मछलियों से भरी हुई थी, को सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी।

समस्याओं के निराकरण के बजाए अखाड़ा बनी संसद

देश में मौजूद गंभीर मुद्दों पर चर्चा और उनके समाधान के प्रयासों के बजाए निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए संसद में दलगत राजनीति भारी पड़ रही है। संसद सत्तारुढ़ और विपक्ष के लिए अखाड़ा बनी हुई है। देश के कर्णधारों को देश की बिगड़ती दिशा—दशा की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और अन्य शोधों के अनुसार, वायु प्रदूषण न केवल श्वसन प्रणाली, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। जहरीली हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से तनाव, चिंता, अवसाद (डिप्रेशन), संज्ञानात्मक हानि और बच्चों में एडीएचडी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसे विशेषज्ञ एक 'मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल' मान रहे हैं।

एरोसोल सूक्ष्म कणों पीएम 2.5 और जहरीली गैसों से दिमागी सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जो अवसाद और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। प्रदूषण के कारण वयस्कों में भावनात्मक थकान, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और बच्चों में सीखने में कठिनाई देखी जा रही है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे तंत्रिका अपक्षयी विकारों का खतरा बढ़ जाता है। अध्ययन बताते हैं कि पीएम 2.5 के एरोसोल घटक, डिप्रेशन और चिंता से सीधे जुड़े हैं। एम्स की एक अन्य रिसर्च में स्पीच एनालिसिस तकनीक के जरिए डिप्रेशन की पहचान की जा रही है, जो बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रदूषण का असर कितना गहरा है। विशेषज्ञों के अनुसार, स्मॉग के दौरान बाहर निकलने से बचें, मास्क का उपयोग करें, घर में एयर प्यूरीफायर लगाएं और तनाव कम करने के लिए योग व स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

इसी तरह इंडियन साइकियाट्रिक सोसायटी की 77वीं वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने बताया कि आज भारत में करीब 60 प्रतिशत मानसिक रोग 35 साल से कम उम्र के लोगों में पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्योंकि यही उम्र पढ़ाई पूरी करने, करियर बनाने और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की होती है। अगर इसी समय मानसिक समस्याएं शुरू हो जाएं और उनका इलाज न हो, तो इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। कांफ्रेंस में यह भी बताया गया कि कोविड-19 महामारी, आर्थिक अस्थिरता और बदलती सामाजिक संरचना ने युवाओं के तनाव को और बढ़ा दिया है। महामारी के बाद पढ़ाई, नौकरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने चिंता और डिप्रेशन के मामलों में इजाफा किया है।

जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांकः2026 में सिंगापुर पहले स्थान पर काबिज है, वहीं भारत 16वें नंबर पर है। रिपोर्ट में यह आंका गया है कि कोई देश अपने लोगों और पूरी दुनिया के लिए कितना जिम्मेदार है। इस सूची में सिंगापुर को दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश घोषित किया गया है। सिंगापुर ने शासन, समाज और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करके पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह साल 2026 के ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत 48.0 के स्कोर के साथ इस फेहरिस्त में 32वें स्थान पर है। यह पिछले साल के मुकाबले दो स्थान नीचे और 1.8 अंक कम है। सॉफ्ट पावर किसी देश की उस क्षमता को कहते हैं, जिसमें वह सैन्य बल के बजाय अपनी संस्कृति और मूल्यों से दूसरे देशों को प्रभावित करता है।

विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान और घरेलू आतंरिक चुनौतियों पर चर्चा और इनके समाधान के बजाए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच संसद तमाशा बनी हुई है। सांसद देश की वास्तविक समस्याओं पर चर्चा करने के बजाए गरिमा को तार—तार करने में लगे हुए हैं। संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके, जिसके बाद उन्हें सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव पर हुई, जिसे सदन ने मंजूर कर लिया। दरअसल, राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने पर विपक्षी दल भड़क गए थे और हंगामा शुरू कर दिया था। इस मामले में कुल आठ सांसदों पर कार्रवाई हुई और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

लोकसभा में पीएम मोदी का अभिभाषण होना था, उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इसके लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंच भी चुके थे। लेकिन उनका अभिभाषण शुरू होने से पहले ही सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। भारत- यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया था, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पीयूष गोयल ने इस दौरान कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर कहा कि इसमें किसानों के हितों को सुरक्षित रक्षा गया है। इससे पहले राहुल गांधी आज फिर संसद में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की वो किताब लेकर पहुंचे। लोकसभा में लगातार हंगामा होता रहा।

अब कमंडल ही मंडल हो गया

हरिशंकर व्यास

पहले कानून के हिसाब से देखें तो भारत में माना जाता है कि हर अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। लोग उसमें लूप होल्स निकाल ही लेते हैं।

यह सवाल इसलिए है क्योंकि भाजपा सरकार ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से ऐसा नया नियम जारी कराया, जिससे देश के करीब ढाई हजार उच्च शिक्षा संस्थानों की तस्वीर बदल जाती। यह कहना अतिरंजित लग सकता है लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर यूजीसी के नियम उसी रूप में लागू होते, जिस रूप में उनको जारी किया गया था तो देश के उच्च शिक्षण संस्थान नब्बे के दशक का बिहार और उत्तर प्रदेश बन सकते थे। लालू यादव की पार्टी की एक प्रवक्ता ने इसका इशारा भी किया था। जब इन नियमों के हवाले उससे पूछा गया कि इसके जरिए तो अगड़ी जाति के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है तो उसने दो टूक अंदाज में कहा कि इनको फंसाया जाना चाहिए क्योंकि ये 90 फीसदी बहुजन के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसने हजारों साल के दमन, अत्याचार वगैरह की बातें भी कहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के नियमों पर रोक लगाई तो सुनवाई के दौरान लालू यादव की पार्टी की प्रवक्ता के उस बयान का भी जिक्र एक वकील ने किया था।

पहले कानून के हिसाब से देखें तो भारत में माना जाता है कि हर अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है। लोग उसमें लूप होल्स निकाल ही लेते हैं। लेकिन जब कानून ही खराब हो तो क्या होगा? तब तो उस कानून के दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। फिर तो उसके सदुपयोग से भी लोगों को फंसाया जा सकता है या किसी को बचाया जा सकता है। यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए थे वो नियम इस दूसरी श्रेणी में आते हैं। वे इतने खराब हैं कि उनके दुरुपयोग की जरुरत नहीं है। उनके सदुपयोग से भी देश के एक छोटे से जातीय समूह के छात्रों और शिक्षकों को फंसाया जा सकता है और उनके करियर पर ग्रहण लगाया जा सकता है।

ध्यान रहे शिक्षण संस्थानों में किसी तरह का भेदभाव रोकने के नियम पहले से बने थे। यूपीए सरकार के समय यूजीसी ने 2012 में नियम बनाए थे, जिनमें सभी छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के प्रावधान किए गए थे। लेकिन 2026 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय जो नियम जारी किए गए उसमें कई चीजें बदल दी गईं। पहले नियम में सिर्फ भेदभाव की बात कही गई थी, जबकि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की बात जोड़ दी गई और सामान्य वर्ग को छोड़ कर बाकी सबको भेदभाव के संभावित शिकार के तौर पर परिभाषित किया गया। इसी तरह पुराने नियम में गलत शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया।

इस तरह गलत शिकायत करके किसी को फंसाने का लाइसेंस दिया गया। पुराने नियम में शिकायत सुनने वाली कमेटी में सभी वर्गों के सदस्य रखने का प्रावधान था, जबकि नए नियम में एससी, एसटी, ओबीसी सदस्य रखने को अनिवार्य किया गया और सामान्य वर्ग का सदस्य रखने की अनिवार्यता नहीं रखी गई। नए नियम में भी रैगिंग को शामिल नहीं किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर रैगिंग का शिकार सामान्य वर्ग का कोई लड़का शिकायत करे तो क्या उसके ऊपर भी भेदभाव की कार्रवाई हो सकती है।

सवाल है कि क्या यूजीसी ने बिना सोचे समझे ये नियम जारी कर दिए या कोई ऐसा बैठा है, जिसके मन में सामान्य वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह है और उसने सबक सिखाने के लिए इस तरह के नियम बनाए या सोच समझ कर राजनीतिक योजना के तौर पर ये नियम बनाए गए ताकि राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं के हाथ से बहुजन राजनीति का कार्ड छीना जा सके? ध्यान रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बहुत सावधान हो गई है। उससे पहले भाजपा अपने को अजेय मान रही थी और लग रहा था कि कांग्रेस या उसके नेतृत्व में एकजुट विपक्ष भी कभी उसको नहीं हरा पाएगा। लेकिन संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, जाति गणना कराओ आदि के नारे पर विपक्ष ने भाजपा की हवा निकाल दिया। लोकसभा चुनाव में चार सौ सीट हासिल करने के लक्ष्य को पंक्चर किया। 'जितनी आबादी उतना हक का राहुल गांधी का नारा हिट हुआ। तभी पिछड़ा, दलित और आदिवासी की ओर ध्यान गया। पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह 'मुफ्त की रेवड़ी से घबराए उसी तरह जाति वाले दांव से घबराए हुए हैं।

ध्यान रहे नरेंद्र मोदी ने ही 'मुफ्त की रेवड़ी का जुमला बोला था।

उन्होंने कहा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी। लेकिन जब लगा कि 'मुफ्त की रेवड़ी का दांव विपक्ष के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस कर्नाटक जीत गई और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं हार रहे हैं। तो उन्होंने भी सबको खजाना खोलने की इजाजत दी। मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को देश भर में भाजपा ने भी आजमाया। उसी तरह बिहार में जाति गणना हुई और राहुल ने कर्नाटक, तेलंगाना में इसकी घोषणा की तो प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़ कर जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। अगले साल जनगणना होगी, जिसमें 1931 के बाद पहली बार देश भर की जातियों की गिनती होगी। तो क्या अब बाजी पलट गई है? अब विपक्ष एजेंडा सेट कर रहा है और भाजपा व उसकी सरकार उस पर प्रतिक्रिया दे रही है?

ऐसा लग रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के नाम पर जो नियम घोषित किए गए थे वो जाति गणना से आने वाले आंकड़ों को ध्यान में रख कर किए गए थे। पहले से ही सरकार और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन को साधने का प्रयास चल रहा है। उनको मैसेज दिया जा रहा है कि देखो भाजपा और नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए अपने सबसे मजबूत सवर्ण समर्थकों को भी नाराज करने का जोखिम लेने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद में जिस तरह के प्रदर्शन हुए, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों पर लोगों ने जूते चलाए और आग लगाई, मोदी-योगी मुर्दाबाद के नारे लगे उन तस्वीरों ने निश्चित रूप से पिछड़े, दलितों में मोदी के प्रति सहानुभूति जगाई होगी।

आगे पता नहीं क्या होगा लेकिन अगड़ी जातियों ने जिस तरह का उबाल दिखाया और जितनी हिंसक प्रतिक्रिया दी उसका राजनीतिक असर निश्चित रूप से हुआ होगा। मन ही मन पिछडी जातियों ने गांठ बांधी होगी। यह भी ध्यान रखने की बात है कि भाजपा के किसी नेता ने इस नियम के खिलाफ बयान नहीं दिया। कई सवर्ण नेता भी इसे डिफेंड करते रहे। यह अहसान बताते रहे कि मोदी ने अगड़ी जातियों को ईडब्लुएस के तहत 10 फीसदी आरक्षण दिया है। तभी सवाल है कि व्यापक हिंदू समाज की एकता बनाने की बात करने वाली भाजपा और आरएसएस की यह कैसी सोच है? एक तरह 'बंटोगे तो कटोगे के नारे हैं और दूसरी ओर हिंदू समाज को ही अगड़ा और पिछड़ा में बांटने की राजनीति हो रही है। यही काम तो नब्बे के दशक में वीपी सिंह करके गए थे। तब भी अगड़ी जातियों ने ऐसे ही प्रदर्शन किए थे, जिसका लाभ आज तक मंडल की पार्टियों को मिल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी मंडल की पार्टियों से उनका राजनीतिक दांव छीन रहे हैं? हो सकता है क्योंकि उनके समर्थक भी कहते हैं कि उन्होंने मंडल और कमंडल को मिला दिया है। वाजपेयी, आडवाणी, जोशी के समय दोनों अलग थे लेकिन अब कमंडल ही मंडल हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है अगड़ी जाति के अपने वोकल समर्थकों को नाराज कर भाजपा पहले से विभाजित पिछड़े, दलित और आदिवासी वोट के सहारे चुनाव जीत पाएगी? ध्यान रहे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने पहले ही 15 फीसदी मुसलमानों, करीब चार फीसदी ईसाई और दो फीसदी सिख यानी 21 फीसदी अल्पसंख्यकों को अपने से अलग कर दिया है। अब 15 फीसदी ही सही लेकिन अगड़े भी अलग होते हैं या उनका मोहभंग होता है तो क्या भाजपा को इसका नुकसान नहीं होगा?

टिप्पणी

औशंकराचार्य वाला विवाद खड़ा

सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि साजिश के तहत यूजीसी के नियम जारी किए गए। औशंकराचार्य वाला विवाद खड़ा किया गया। कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने और उनके सबसे निष्ठावान वोट को उनसे अलग करने के लिए किसी ने अंदर से साजिश की और यूजीसी का नियम जारी हुआ। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को इसका अंदाजा हो गया इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने का विरोध नहीं किया। सवाल है कि जिस पार्टी में नेता, मंत्री, अधिकारी सब ऊपर के आदेश से ही सांस लेते हैं वहां किसने ऐसा करने की साजिश की?

भाजपा इकोसिस्टम के लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बना रहे हैं। वे पिछड़ी जाति से आते हैं और खुल कर पिछड़ा राजनीति करने में यकीन करते हैं। कहा जा रहा है कि ओडिशा का मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बाद जब भाजपा का अध्यक्ष पद भी हाथ से निकला तो संसदीय समिति की सिफारिशों में अदलाबदली करके प्रधान ने ऐसा नियम जारी करवा दिया, जिससे पार्टी फंसी। शंकराचार्य वाले मामले को दिल्ली बनाम लखनऊ के विवाद और साजिश के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पर सब कुछ हुआ है।

यूजीसी नियमों में साजिश का दूसरा पहलू दिल्ली बनाम लखनऊ के विवाद के तौर पर पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जान बूझकर अगड़ा बनाम पिछड़ा का मुद्दा बनाया गया और अगड़ों के विरोध को खूब फैलाया गया। ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में बाकी किसी भी राज्य के मुकाबले अगड़ी जातियां खास कर ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार सबसे ज्यादा हैं। अगर वे भाजपा से नाराज होते हैं तो अगले साल के चुनाव में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इसका उलटा हो गया तो क्या होगा? अगर अगड़े नाराज हुए और सचमुच पिछड़े भाजपा के पक्ष में गोलबंद हो गए तब तो यह दांव मास्टरस्ट्रोक बन जाएगा?

हालांकि साजिश थ्योरी वाले इसे नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि 18 फीसदी मुस्लिम और 10 फीसदी यादव तो पूरी तरह से सपा के साथ हैं। 20 फीसदी दलितों में से हर हाल में 10 फीसदी दलित मायावती का साथ देंगे। अगर 20 से 22 फीसदी सवर्ण भाजपा से छिटके तो भाजपा बुरी तरह से हारेगी। तभी साजिश थ्योरी वाले इसे योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की साजिश के तौर पर देख रहे हैं।

इसी तरह, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पिछले दिनों देश के एक बडे उद्योगपति के यहां जाने की तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए यह साजिश रची गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य के प्रति सद्भाव दिखाया और उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। इस पर कहा जा रहा है कि वे दिल्ली के नेता के करीबी हैं। इसलिए उन्होंने अलग लाइन पकड़ी।

अब सवाल है कि अगर कोई साजिश थी तो योगी आदित्यनाथ को किसने रोका था कि वे अपने प्रशासन के लोगों को शंकराचार्य के पास भेजें और मामला खत्म कराए? उनको मनाने का जो काम शंकराचार्य के माघ मेला छोड़ने के बाद किया गया वह पहले भी हो सकता था। जो हो इन दोनों घटनाओं ने देश की राजनीति में नए सिरे से ध्रुवीकरण की संभावना को जन्म दिया है। तभी यह भी माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यथास्थिति को तोड़ते रहते हैं ताकि समाज और राजनीति में उथलपुथल मचा कर अपनी लोकप्रियता कायम रखे।

ब्लॉग यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस (12 फरवरी) पर विशेष

खुलकर अपनों से बात करें और समस्या का उचित समाधान पाएं

किशोरावस्था बदलाव का दौर, जिज्ञासाओं को शांत करना जरूरी

मुकेश कुमार शर्मा

देश की आधी आबादी यानि महिलाओं और खासकर किशोर-किशोरियों (10 से 19 वर्ष) को पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का समुचित लाभ उठाने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं और किशोर-किशोरियां आगे भी आ रही हैं किन्तु कुछ भ्रांतियों के चलते आज भी कई बीमारियों या रोगों के बारे में वह खुलकर बात करने से अपनों तक से कतराते हैं या झिझक महसूस करते हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल है यौन जनित रोग (संक्रमण), जिसके बारे में वह अपनों से भी बात करने से हिचकते हैं। इस बारे में जागरूकता लाने और भ्रांतियों को जड़ से मिटाने के लिए ही हर साल 12 फरवरी को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है।

किशोरावस्था शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों का दौर होता है, ऐसे में देश के इन कर्णधारों को सही दिशा दिखाने के लिए भी आज का यह खास दिन बहुत मायने रखता है। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सुनी-सुनाई बातों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के भरोसे किशोर-किशोरियों को छोड़ने से बेहतर है कि उनसे खुलकर बात करें और उनकी जिज्ञासाओं को शांत करें ताकि उनके सुनहरे भविष्य का रास्ता तैयार हो सके। इसी उद्देश्य से स्कूलों में किशोर/किशोरियों की काउंसिलिंग की व्यवस्था की जाती है। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक और साथिया केंद्र किशोरावस्था के बारे में सही जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं का निदान भी करते हैं। इसके अलावा निकटतम सरकारी अस्पतालों के चिकित्सकों, आशा, एएनएम और घर के निकट स्थित आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की भी ऐसे में मदद ली जा सकती है।

इस दिवस का मूल मकसद किशोर-किशोरियों और महिलाओं को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी समुचित जानकारी मुहैया कराना है।

इस दिवस का मूल मकसद किशोर-किशोरियों और महिलाओं को यौन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में भी समुचित जानकारी मुहैया कराना है। गर्भ निरोधक साधनों के फायदे समझाने के साथ ही परिवार नियोजन के बारे में जागरूक बनाना है ताकि महिलाएं खुद से निर्णय लेने में सक्षम बन सकें कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। यौन संचरित संक्रमण (एसटीआई) एक बड़ी समस्या है किन्तु लोग इस मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं, जिसका असर किशोर-किशोरियों और दम्पति के प्रजनन स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को केवल शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे मानसिक और सामाजिक सरोकारों से भी जोड़कर देखने की आवश्यकता है। इसके लिए सुरक्षित गर्भनिरोधक विधियों के बारे में शिक्षित करने के साथ ही यौन संचरित संक्रमण और एचआईवी की रोकथाम और उनके लक्षणों और बचाव के बारे में भी समझ को विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा गर्भ न ठहरना या बच्चा न होने की समस्या को लेकर भी लोगों की भ्रांतियों को दूर किया जाना चाहिए और इस बारे में अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए। सर्वाइकल और कैंसर की स्क्रीनिंग 30 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं का अवश्य हो ताकि इस गंभीर बीमारी से आधी आबादी को आसानी से बचाया जा सके। इसमें जरूरी टीकाकरण की भी अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही यौन हिंसा और भेदभाव जैसी स्थितियों से उबारकर किशोर-किशोरियों और महिलाओं को शारीरिक, मानसिक स्वस्थ्य प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आज का यह खास दिन हम सभी को प्रेरित करता है।

आज के समय में तमाम गर्भनिरोधक साधनों की मौजूदगी के बाद भी अनचाहा गर्भ धारण करना और असुरक्षित गर्भपात की स्थितियां इस ओर साफ़ इशारा करती हैं कि अभी इस मुद्दे पर समुदाय को जागरूक बनाने की सख्त जरूरत है। इसकी शुरुआत घर के बड़े-बुजुर्गों से होनी चाहिए ताकि वह अपनी आने वाली पीढ़ी को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बता सकें और संकोच व झिझक से बाहर निकलकर इस गंभीर मुद्दे पर बात करने में सहज महसूस कर सकें। महिलाओं को रजोनिवृत्ति (मेनोपाज) से होने वाले शारीरिक बदलावों और दिक्कतों आदि के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए।

(लेखक पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं)

खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर दो युवकों की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात में खड़े ट्रक से बाइक पर सवार तीन युवक टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। जबकि घायल को एम्बुलेंस की मदद से रामपुर पीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया।परिजन उसको आनन-फानन में लेकर भदोही जिले के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उसको आईसीयू में रखा गया है। तीनों बाइक सवार वाराणसी में बारात से वापस आ

रहे थे। पुलिस ने ट्रक और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है। घटना नेवढ़िया थाना क्षेत्र के नोनारी गांव स्थित बाबतपुर-जमालापुर मार्ग का है। मृतकों की पहचान 39 वर्षीय कैलाश पटेल पुत्र कमला पटेल और 29 वर्षीय अरुण पटेल पुत्र लालबहादुर पटेल के रूप में हुई है। जबकि घायल की पहचान 30 वर्षीय विनोद पटेल पुत्र अमरनाथ के रूप में हुई है। यह तीनों रसुलहा गांव के निवासी हैं।यह तीनों गांव के ही युवक के बारात में मंगलवार को वाराणसी जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के तड़सड़ा गए थे। वहां से रात में खाना खाने के बाद तीनों एक ही बाइक पर 11 बजे घर को निकल थे। लेकिन बाबतपुर-जमालापुर मार्ग पर नोनारी तिराहे के पास खड़े ट्रक में उनकी बाइक जा टकराई। हादसे में कैलाश और अरुण की मौत हो गई।ज्ञात हो कि मृतक अरुण अपने पिता का अकेला लड़का था। उसकी तीन महीने पहले शादी हुई थी। पिता होमगॉर्ड के रूप में नेवढ़िया थाने में तैनात हैं। इसके अलावा मृतक कैलाश घर पर रहकर खेती-बाड़ी करते थे। उनके तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा सुनील मुंबई में रहता है। जबकि उनके दो अन्य बच्चे गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक : धनज्य सिंह

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मां शारदा इंटरमीडिएट बालिका विद्यालय खानापट्टी का वार्षिकोत्सव समारोह बुधवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद धनंजय ने विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह प्रिंसू के निधि से निर्मित स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय का लोकार्पण किया। छात्राओं ने आपरेशन सिंदूर, बेटी हिंदुस्तान की व भगत सिंह पर एकांकी प्रस्तुत कर देशभक्ति का वो जज्बा प्रस्तुत किया कि लोग भाव विश्वल हो गए। अपने संबोधन में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। शिक्षा और संस्कार के संगम से ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण होता है। जिससे युवा सही दिशा में विकास कर सके और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह प्रिंसू ने कहा कि शिक्षित और संस्कारित नागरिक ही एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र की नींव रखते है। अतिथियों ने यूपी बोर्ड परीक्षा हाईस्कूल इंटरमीडिएट में जनपद की टाप टेन सूची में शामिल छात्रा आयुषी शुक्ला, अंशिका उपाध्याय व महिमा कन्नौजिया को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किया। विद्यालय के प्रबंधक जगदीश नारायण सिंह एडवोकेट ने प्रगति आख्या प्रस्तुत करने के साथ ही अभ्यागतों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। अध्यक्षता पूर्व प्रमुख सुधाकर उपाध्याय ने किया। संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य शरद सिंह व आभार प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने ज्ञापित किया। वक्ताओं में ब्लाक प्रमुख संजय सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक रमेश सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह, प्रधानाचार्य डा.जंग बहादुर सिंह, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष फौजदार सिंह अखिलेश, श्यामधर मिश्र, विकास सिंह, अंकुर दुबे, सुशील सिंह आदि रहे।

संक्षेप

पूर्व डीआईजी की माता की तेरहवीं पर लगा जमावड़ा

जौनपुर। जिले के सुरेरी क्षेत्र के भदखिन गांव निवासी पूर्व डीआईजी राधेश्याम विश्वकर्मा की माताजी स्वर्गीय बरफी देवी की तेरहवीं (त्रयोदशाह) के अवसर पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा एवं ब्रह्मभोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ-साथ राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तियों की भी उपस्थिति रही।श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने स्व. बरफी देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपस्थित लोगों ने उनके सादगीपूर्ण, धार्मिक एवं त्यागमय जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें परिवार और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया। पूर्व डीआईजी राधेश्याम विश्वकर्मा कहा कि गांव के साधारण परिवेश में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर पुलिस विभाग में डीआईजी जैसे उच्च पद तक पहुंचने की यात्रा उनकी माता के त्याग, संस्कार और प्रेरणा का परिणाम है।

अनमैप्ड मतदाताओं के साक्ष्य मिलान में तेजी लायें

जौनपुर। जिलाधिकारीध्जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र द्वारा कार्यालय खंड विकास अधिकारी रामनगर के सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसआईआर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत बीएलओ और सुपरवाइजर को लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज सहित अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ और सुपरवाइजर से अब तक निर्गत नोटिसों की संख्या, नोटिस वितरण की स्थिति, डाटा फीडिंग, जनसुनवाई, साक्ष्य मिलान, लॉजिकल डिसक्रिपेंसीज सहित अन्य बिंदुओं पर अद्यतन प्रगति की जानकारी प्राप्त की।

मील का पत्थर साबित होगा बजट : कृपा शंकर सिह

जौनपुर। उत्तर प्रदेश में पेश 9.13 लाख करोड़ रुपये के बजट में खजाना खोलते हुए योगी सरकार ने तोहफों की बारिश कर दी जिसमें जौनपुर जिले को काशी,विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में शामिल किया है जो जौनपुर के लिए एक उपलब्धि है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज इस प्राधिकरण के गठन की घोषणा करते हुए जौनपुर को भी इसमें शामिल करने की घोषणा की। इस कदम से जिले के विकास को गति मिलेगी। जिसको लेकर जौनपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं पूर्व गृहराज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह ने सरकार का आभार जताया है।

हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा

जौनपुर। जफराबाद थाना क्षेत्र के कीरतापुर गांव निवासी 22 वर्षीय रवि सोनकर पुत्र लल्ला सोनकर, जीजा सोनू के साथ बाइक से धर्मापुर में मार्केट करने के लिए आया हुआ थे। इसी दौरान धर्मापुर और कबीरउद्दीनपुर गांव के मध्य बाइकों की भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गये।जिसकी उसकी वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।जबकि जीजा सोनू मामूली रूप से जख्मी हुए दूसरा बाइक सवार भी चोटिल हो गया। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। रवि सोनकर की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

नैतिक मूल्य और सामाजिक समरसता जरूरी : कुलपति

जौनपुर(आरएनएस)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के संकाय भवन स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' भारतीय चिंतन की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समन्वित विकास की परिकल्पना प्रस्तुत की। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शैक्षणिक उन्नयन तक सीमित नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी सुदृढ़ करना है।

मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल, दूसरा फरार

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। मीरगंज पुलिस टीम ने बुधवार की सुबह मुठभेड़ के दौरान गो. तस्करी करने वाले अंतर्जनपदीय एक गौतस्कर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया बदमाश फरार चल रहा था। बदमाश के फायर करने पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में फायर कर दिया। पुलिस की गोली गौतस्कर बदमाश के पैर में लगने से वह घायल हो गया है। पुलिस ने कब्जे से एक मोटर साईकिल व अन्य समान बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार बीते मंगलवार 10 फरवरी को एक पिकअप पर सवार दो अपराधी जिसमें से एक अपराधी मो सलमान पुत्र मेराज निवासी ग्राम माहुल थाना अहरौला जिला आजमगढ़ को गोली लगी थी घायल अवस्था में मौके से मय पिकअप के गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार उसमे शामिल दूसरा अपराधी मोनू उर्फ बलवन्त बघेल पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम रामनगर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर का फायदा उठामे हुए मौने फरार हो गया था जो उक्त मुकदमे में वांछित चल रहा था। उसे जल्द पकड़ लिया जायेगा।

मथुरा डीएम का कड़ा रुख : आईजीआरएस में लापरवाही पर 15 अधिकारियों को नोटिस

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। डीएम सीपी सिंह ने मंगलवार को राजस्व और सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीएम ने जिले के 15 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

डीएम ने एलडीएम, सीएमओ, बीएसए, डीआईओएस, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा विभाग), एएमए जिला पंचायत, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एडीओ पंचायत राया, अधिशासी अभियंता सिंचाई मांट ब्रांच सहित फरह, राधाकुंड व नंदगांव के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिए हैं। साथ ही इन्हें

पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की सख्त हिदायत दी है।

सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में में रहें उपस्थित

डीएम ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याएं सुनें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि ही प्राथमिकता है और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

अनुपस्थित अधिकारियों पर भी कार्रवाई के दिए निर्देश

राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी एसडीएम को फार्मर्स रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने, राजस्व वादों का समय से निस्तारण करने और पांच साल से अधिक समय से लंबित मुकदमों को अभियान चलाकर खत्म करने को कहा। उन्होंने स्टांप, विद्युत, परिवहन, खनन और आबकारी विभागों को राजस्व वसूली का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने का आदेश दिया।

बैठक में एडीएम वित्त डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा, एडीएम प्रशासन अमरेश कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन समेत सभी एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे।

करंट से निविदाकर्मी की मृत्यु की जांच करेंगे तीन अभियंता, विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम को दी गई मामले की जानकारी

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। तिवारीपुर क्षेत्र में करंट से निविदाकर्मी की मृत्यु के मामले की तीन अभियंताओं की कमेटी जांच करेगी। अधीक्षण अभियंता शहर रणजीत चौधरी ने मोहद्दीपुर के अधिशासी अभियंता, राप्तीनगर के एसडीओ और टाउनहाल के सहायक अभियंता मीटर को जिम्मेदारी दी है।

सईद अब्दुल्ला नगर भट्ठा पीपल निवासी राजू उर्फ मो. सलीम बिजली निगम में अकुशल कर्मचारी के रूप में तकरीबन 20 वर्ष से काम कर रहे थे। उनकी नियुक्ति सीढ़ी मैन के पद पर थी। वह तिवारीपुर उपकेंद्र में तैनात थे। सोमवार दोपहर 1:07 बजे मोहनलालपुर में गड़बड़ी ठीक करने दो अन्य सीढ़ी मैन के साथ पहुंचे थे।

बताया गया था कि ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है। साथ में गए कर्मचारियों का कहना है कि राजू

अचानक सीढ़ी पर चढ़ गए। अभी शटडाउन नहीं लिया गया था। इसके बाद करंट की चपेट में आ गए। अभियंताओं का कहना है कि सूरजकुंड के सब स्टेशन आपरेटर के पास भी शटडाउन के लिए कोई काल नहीं आयी थी। इससे मामला उलझ गया है।

जिसकी जिम्मेदारी, उस पर हो कार्रवाई

विद्युत संविदा मजदूर संगठन और विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता शहर रणजीत चौधरी से मुलाकात की। उन्हें घटनाक्रम से अवगत कराया और मृत निविदाकर्मी के स्वजन को अविलंब 10 लाख रुपये की सहायता की मांग की।

विद्युत मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष अजय शाही ने कहा कि जांच जल्द पूरी कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। घटना की जानकारी के बाद भी एसडीओ सुरेंद्र रस्तोगी मौके पर नहीं पहुंचे। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। आरोप लगाया कि सूरजकुंड के एसडीओ आए दिन निविदाकर्मियों का उत्पीड़न करते हैं। असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं।

पद के अनुरूप ही कराएं कार्य

श्री गोरखनाथ खंड के अधिशासी अभियंता अतुल रघुवंशी ने कहा कि सभी एसडीओ और जेई को निर्देश दिए गए हैं कि वह कर्मचारियों से उनके पद के अनुरूप ही कार्य कराएं। सभी कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों से लैस रहें। इसकी जिम्मेदारी अवर अभियंता की है। एसडीओ और जेई की दो सदस्यीय कमेटी यह बताए कि कौन से कर्मचारी पोल पर चढ़कर अनुरक्षण कार्य में दक्ष नहीं हैं। ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट दी जाए।

स्वाधीन सिंह हत्याकांड में पुलिस पर गंभीर आरोप

जौनपुर। बदलापुर के बहुचर्चित स्वाधीन सिंह हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। जनता की अदालत के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करने निकले पीड़ित परिवारों को जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, तो मामला और भी गर्मा गया। विद्यावती रिसॉर्ट से लेकर तहसील मुख्यालय तक घंटों चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय हिंदू मित्र परिषद के अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट अरविंद कुमार पांडेय के नेतृत्व में बुधवार को विद्यावती रिसॉर्ट में जनता की अदालतश का भव्य आयोजन होना था। इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही थी। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू होने से ऐन पहले रिसॉर्ट के लॉन में ताला जड़ दिया और आयोजन पर रोक लगा दी। पुलिस का तर्क था कि इस आयोजन के लिए प्रशासन से अग्रिम वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी।

गोरखपुर मतदाता सूची में 'लाजिकल डिसक्रिप्शन' से होगी बड़ी सफाई, BLO करेंगे सत्यापन

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआइआर अभियान के तहत अब 'लाजिकल डिसक्रिप्शन' प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज उन तकनीकी और तर्कहीन त्रुटियों को चिन्हित कर सुधारना है, जो सामान्य डेटा पैटर्न के आधार पर असंभव या संदिग्ध प्रतीत होती हैं।

उदाहरण के तौर पर यदि मतदाता सूची में किसी पिता की आयु 15 वर्ष दर्ज है, जो स्पष्ट रूप से डेटा एंट्री की त्रुटि दर्शाता है। इसी तरह एक ही व्यक्ति से छह या उससे अधिक मतदाताओं को बच्चों के रूप में जोड़े जाने जैसी असामान्य प्रविष्टियां भी जांच के दायरे में हैं। आयोग का उद्देश्य इन विसंगतियों को दूर कर मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाना है।

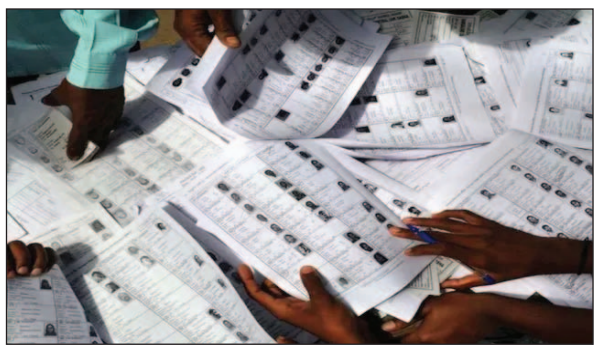

जिले में अब तक करीब छह लाख मतदाताओं के नाम इस प्रक्रिया के तहत चिन्हित किए गए हैं। संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, हालांकि उन्हें किसी प्रकार की व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने आयु, पारिवारिक संबंध या अन्य विवरण से जुड़े आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) को उपलब्ध करा देंगे। बीएलओ दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सूची में आवश्यक संशोधन करेंगे। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी आधार पर संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य किसी का नाम हटाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में शुद्ध और अद्यतन सूची का उपयोग किया जा सके।

भदोही में पुलिस मुठभेड़ में प्रयागराज के तीन बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली

आर्यावर्त संवाददाता

भदोही। कोइरौना पुलिस की मंगलवार की रात पैगहां गांव के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से पांच हजार का इनामी बदमाश प्रयागराज जिले के हंडिया थाना के बिलारी गांव निवासी संदीप यादव घायल हो गया।

उसके साथ दो अन्य बदमाश प्रयागराज का ही भेलसी गांव का जयप्रकाश यादव व 17 वर्षीय किशोर गिरफ्तार किया गया।

घायल बदमाश के ऊपर प्रयागराज, भदोही के विभिन्न थानों में लूट, छिनैती, चोरी के 12 मुकदमे दर्ज हैं। उनके पास से एक काले रंग की यामहा बाइक, 12 बोर का एक तमंचा, एक खोखा, एक कारतूस, प्लास, पेचकस और चाकू बरामद किया।

कोइरौना थानाध्यक्ष रामनगीना यादव अपनी टीम संग रात्रि में लगभग एक बजे गश्त पर थे। सीतामढ़ी की ओर से एक बाइक को देखकर पुलिस ने बारीपुर नहर के पास बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने बाइक की गति बढ़ा दी।

थानाध्यक्ष ने मोबाइल टीम को सूचना देकर उनका पीछा किया तो पीछे बैठे किशोर ने पुलिस वाहन पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बीच में बैठे संदीप यादव के पैर में गोली लगी। इससे बाइक चालक लड़खड़ाकर सड़क किनारे गिर पड़ा और तीनों लुढ़ककर गड्ढे में जा गिरे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, पूछताछ में पता चला कि तीनों लूट, छिनैती और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।

पड़ोसी जनपद के होने के की वजह से वह भदोही के सीमावर्ती दुकानों, लूट आदि की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल बदमाश बदमाश को डीघ सीएचसी में भर्ती कराया गया है। उसके साथियों से पूछताछ की जा रही है।

एनई रेलवे मेंस कांग्रेस पंजीकरण विवाद की जांच शुरू, कर्मचारियों में उबाल

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के पंजीकरण प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स कानपुर ने गोरखपुर उप श्रमायुक्त कार्यालय से परीक्षण आख्या मांगी है। रेल कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता सुभाष दूबे की शिकायत पर रेलवे प्रशासन ने भी जांच शुरू करा दी है।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के निर्देश पर जांच के लिए इंस्पेक्टर नामित कर दिए गए हैं। सांसद विजय कुमार दूबे ने फर्जी ढंग से रेल कर्मचारी संगठन बनाने व पंजीकृत कराने की जांच के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) को चिट्ठी लिखी है। मेंस कांग्रेस के पंजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठन उतर आए हैं। संगठनों ने भी रेलवे प्रशासन से जांच

की मांग की है।

उधर, मंगलवार की रात एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के सिग्नल कारखाना पर लगे बोर्ड पर कालिख पोत दी गई। इसे कर्मचारियों में उपजे आक्रोश का परिणाम माना जा रहा है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोरखपुर संतोष कुमार त्रिपाठी ने पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल खजांची राकेश सिंह को पत्र लिखकर 13 फरवरी को सुबह 11 बजे कार्यालय बुलाया है।

उन्होंने अवगत कराया है कि जो विधान संशोधन आदेश 15 सितंबर 2025 को तत्काल निलम्बित करने और प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश प्रदान करने के संबंध में है, पर रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा पुनः विधिवत परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके अनुपालन में प्रकरण में पुनः जांच किए जाने से पूर्व आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

ताकि, अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सांसद कुशीनगर विजय कुमार दूबे ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखा है। उन्होंने महाप्रबंधक से कहा है कि कतिपय रेल कर्मचारियों के फर्जी हस्ताक्षर से रेल कर्मचारी संगठन बनाने एवं उसे पंजीकृत कराने तथा उसके आधार पर चुनाव लड़कर मान्यता प्राप्त कर रेल यूनियन की सुविधा प्राप्त करने की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराएं। साथ ही दोषी व्यक्तियों पर विधिक एवं अनुशासनिक कार्यवाही कर अवगत भी कराएं।

एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) ने एनई रेलवे मेंस कांग्रेस के पंजीकरण प्रकरण को रेलवे प्रशासन से लगायत आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआइआरएफ) और रेलवे बोर्ड को अवगत कराया है। यूनियन के महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी का कहना है कि एआइआरएफ के माध्यम से इस प्रकरण को रेलवे बोर्ड के सामने होने वाली स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में उठाया जाएगा।

उन्होंने रेलवे प्रशासन से यथाशीघ्र मामले की जांच पूरी कर कर्मचारी संगठन के नाम पर रेलवे प्रशासन को गुमराह करने वाले रेलकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी नेता अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि एनई रेलवे मेंस कांग्रेस की साधारण सभा 637 सदस्यों का मतलब यह हुआ कि इनके प्राथमिक सदस्यों की संख्या 159250 है। किसी भी यूनियन की साधारण सभा की बैठक में जाने वाले रेलवे कर्मचारियों को अपने अनुशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए।

मान्यता प्राप्त करने के बाद अभी जनवरी माह की 19 तारीख को इनकी साधारण सभा की बैठक हुई है, जिसमें 318 या 319 साधारण सभा के सदस्यों ने भाग लिया था, यह भी संभव नहीं है। मान्यता प्राप्त संगठन की इस साधारण सभा की बैठक की जानकारी रेलवे प्रशासन को नहीं है। यह भी आश्चर्यजनक है।

रात में सोते समय बेड पर यूरिन कर देता है बच्चा, पेरेंट्स इस तरह से दें ट्रेनिंग

5 से 7 साल की उम्र में भी बच्चा अगर रात को सोते वक्त बिस्तर पर ही यूरिन पास कर देता है तो इसके पीछे अनुवांशिकता हो सकती है या फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी ये समस्या हो जाती है। हालांकि बहुत सारे मामलों में सिर्फ पेरेंट्स को बच्चे की सही ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा भी बिस्तर गीला कर देता है तो जान लें कि इससे निपटने के लिए क्या करें।

छोटे बच्चों का रात में बिस्तर गीला करना यानी बेड पर यूरिन पास कर देना। इसे 'नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस' कहते हैं, जो बचपन में नॉर्मल होता है। बड़े होने के साथ ही धीरे-धीरे बच्चे डेली रूटीन की आदतों को सीख जाते हैं। 5 साल के होते-होते ज्यादातर बच्चे बेड पर यूरिन करना बंद कर देते हैं। 5 वर्ष की उम्र में तकरीबन 15 प्रतिशत बच्चे ही होते हैं जो रात में सोने के दौरान बेड पर यूरिन कर देते हैं। 4 से 5 साल तक अगर बच्चा रात में बेड पर ही सोते वक्त यूरिन पास कर देता है तो इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स कुछ छोटी बातों को ध्यान में रखें तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ बच्चों में ये समस्या 7 साल के बाद भी देखी जाती है। इसको लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस आर्टिकल में जानेंगे कि अगर बच्चा बिस्तर गीला करता है तो आप इससे निपटने के लिए कैसे उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं।

बढ़ती उम्र में भी रात में सोते वक्त बिस्तर पर यूरिन पास करने की समस्या कुछ बच्चों में अनुवांशिक भी हो सकती है। जैसे उनके पेरेंट्स में से किसी एक को ये समस्या रही हो। इसके अलावा भी बहुत सारी वजहें हैं जैसे बच्चे में कमजोरी होना। अगर आपका बच्चा भी रात को सोते वक्त बेड पर टॉयलेट कर देता है तो जान लें कि आप इस समस्या से निपटने में कैसे उसे मदद कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

बच्चे क्यों करते हैं बिस्तर गीला?

जो बच्चे बिस्तर गीला करने की समस्या से जूझ रहे हो उनमें ज्यादातर छोटे बच्चों में नींद में जागने जैसा महसूस होने पर होती है, जैसे कई बार वह सपने में होते हैं, लेकिन उन्हें रियल महसूस होता है। इसके अलावा नींद बहुत ज्यादा गहरी होने के दौरान जब मस्तिष्क संकेत यूरिन ब्लैडर भरने का संकेत नहीं देता है तो बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं। जब बच्चे की उम्र बढ़ती है तो मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच संबंध सही से विकसित हो जाता है। इसके बाद वह बिस्तर पर यूरिन करना बंद कर देते हैं।

सोने से पहले तरल चीजें न दें

हाइड्रेशन हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है, इसलिए दिन में बच्चे को लिक्विड खाने की चीजें, हेल्दी ड्रिंक्स, पानी भरपूर मात्रा में देना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि सोने से कुछ देर पहले आप उसे बहुत ज्यादा तरल चीजें न दें। इससे उसे रात में बार-बार पेशाब आ सकती है और बिस्तर गीला होने के चांस ऐसे में ज्यादा होते हैं।

सोने से पहले यूरिन करवाएं

रात को बच्चा अगर बिस्तर पर यूरिन पास कर देता है तो आपको सोने से ठीक पहले एक बार उसे जरूर टॉयलेट करवानी चाहिए। रोजाना जब पेरेंट्स ये चीज कुछ दिनों तक करवाते हैं तो बच्चा धीरे-धीरे इस आदत में ढल जाता है।

डायपर लगाना बंद करें

बच्चा अगर बिस्तर गीला करता हो तो अक्सर पेरेंट्स डायपर पहनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा भीग जाता है तो उसकी नींद खुलती है। ऐसे में वह जाग जाते हैं और उनका मस्तिष्क संकेत देना शुरू करता है, जिससे बच्चे की बेड पर यूरिन करने की आदत कम होने लगती है। दरअसल जब आप बच्चे को डायपर लगाते है तो ये उनके लिए एक सहारे की तरह काम करता है। इससे उनके दिमाग को ये संकेत मिल सकता है कि उन्हें पेशाब करने के लिए जागने की जरूरत नहीं है।

ड्राई बेड ट्रेनिंग क्या है?

आप बच्चे को ड्राई बेड ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसमें बच्चा और पेरेंट्स दोनों की ही नींद कुछ दिनों तक रात में खराब होती है, लेकिन कई बार ये तरीका कारगर होता है। जैसे आप पहले दिन रात को तकरीबन 1 बजे बच्चे को जगाकर पूछ सकते हैं कि क्या उसे यूरिन करने जाना है। अगर वह मना करे तो भी आप उसे प्यार से ले जाकर वॉशरूम तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से आप देसरे दिन की रात को सोने के करीब तीन-तीन घंटे के बाद जगाएं। तीसरी से पांचवी रात तक एक बार जगाएं। छठी रात तक बच्चे की आदत हो जाएगी कि वह खुद ही जागने की कोशिश करता है।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपका बच्चा एक एज के बाद भी बिस्तर पर यूरिन पास कर देता है तो उसको शर्मिंदा महसूस न करवाएं, बल्कि इस सिचुएशन को प्यार और समझदारी से हैंडल करना चाहिए। अगर आपका बच्चा रात में सोते वक्त बिस्तर गीला नहीं करता है और अचानक ये समस्या शुरू हो जाए तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 7 साल की उम्र के बाद भी बच्चा बेड पर यूरिन पास करता हो तो भी आपको एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत होती है। इसी तरह से बेड ट्रेनिंग के बाद भी अगर सुधार न आ रहा हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए।

केमिकल पीलिंग के बाद ध्यान में रखें ये बातें, त्वचा को नहीं होगा नुकसान

महिलाएं पिछले साल से त्वचा की देखभाल का एक नया रुझान अपना रही हैं, जिसे केमिकल पीलिंग कहा जाता है। यह एक कॉस्मेटिक उपचार है, जिसमें त्वचा की बाहरी परतों को एक्सफोलिएट करने के लिए एक रासायनिक घोल का उपयोग किया जाता है। इसे ऐसे समझें कि इसके जरिए किसी मास्क की तरह मृत त्वचा हट जाती है। इसके बाद नई और मुलायम त्वचा नजर आती है। इस उपचार के बाद इन बातों का विशेष ध्यान रखना अहम होता है।

विस्तार से जानें केमिकल पीलिंग का मतलब

केमिकल पीलिंग के दौरान त्वचा पर एक रासायनिक घोल लगाया जाता है, जिसकी मदद से उसकी बाहरी परत हट जाती है। त्वचा की यह पुरानी और क्षतिग्रस्त परत उतरने के बाद नई और स्वस्थ त्वचा उभरती है। यह ज्यादा निखरी, चमकदार, मुलायम और बेदाग होती है। इस उपचार की मदद से महीन रेखाएं, झुर्रियां और झाइयां कम हो जाती हैं। साथ ही यह मुंहासों के दाग, रंजकता और टैनिंग हटाने में भी मदद करता है।

अन्य सक्रीय सामग्रियों का न करें इस्तेमाल

केमिकल पीलिंग के बाद त्वचा बहुत संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में आपको कई दिनों तक उस पर कोई अन्य सक्रीय सामग्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इनमें रेटिनोइड्स, एएचए, बीएचए, ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड आदि शामिल होते हैं। इन्हें लगाने से नई बनने वाली त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है और हाइपरपिग्मेंटेशन जैसी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। केमिकल पीलिंग के कुछ दिनों बाद तक केवल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ही उपयोग करें।

त्वचा को धूप से रखें सुरक्षित

केमिकल पीलिंग के बाद त्वचा पर बिलकुल धूप न लगने दें। नई त्वचा अल्ट्रा वॉयलेट किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। इनके संपर्क में आने से जलन पैदा हो सकती है, उपचार में बाधा आ सकती है और रंजकता व टैनिंग का खतरा हो सकता है। अगर आपको इस दौरान सनबर्न हो गया तो गंभीर क्षति हो सकती है और गहरे दाग पड़ सकते हैं। ऐसे में सनस्क्रीन लगाएं, चेहरे को ढकें और दिन में घर पर रहें।

त्वचा को छूने और छीलने की न करें गलती

केमिकल पील का असर कुछ दिनों बाद नजर आता है, क्योंकि त्वचा धीरे-धीरे करके फटती है। हालांकि, बाहरी परत खुद ही उतर जाती है, जिसे छीलने की गलती नहीं करनी चाहिए। मृत त्वचा की परतों को छीलने या नोचने से संक्रमण का खतरा रहता है और आसानी से न हटने वाले निशान पड़ सकते हैं। इस उपचार के बाद अपनी त्वचा को ज्यादा छूने से भी बचें, क्योंकि ऐसा करने से कीटाणु फैल सकते हैं।

मेकअप और अन्य फेशियल उपचारों से करें परहेज

केमिकल पीलिंग के एक या 2 दिन बाद तक आपको मेकअप नहीं लगाना चाहिए। मेकअप उत्पाद उपचार प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और जलन, खुजली और शुष्कता का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ हफ्तों तक किसी भी प्रकार का अन्य फेशियल उपचार करवाने की गलती भी न करें। इनमें वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल और लेजर उपचार आदि शामिल होते हैं। ये कॉस्मेटिक उपचार त्वचा में जलन और सूजन पैदा कर सकते हैं।

स्क्वायर फेस शेप पर खूब जचेंगे ये हेयरस्टाइल, वैलेंटाइन पर करें ट्राई

स्क्वायर फेस शेप वाली महिलाओं को अक्सर टेंशन रहती है कि वो कौन सा हेयरस्टाइल बनाएं, जो उन पर सूट करे। क्योंकि स्क्वायर फेस शेप काफी ब्रॉड होता है। चलिए यहां हम आपको कुछ बेस्ट हेयरस्टाइल बता रहे हैं, जो स्क्वायर फेस शेप पर काफी सूट करेंगे।

अगर आपका फेस शेप स्क्वायर है तो आप हाई पोनीटेल बना सकती हैं। करीना कपूर के फेस का शेप भी स्क्वायर है, उन्होंने स्लीक हेयर कर हाई पोनी बनाई है, जो काफी सूट कर रही है। इसे आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस पर बना सकती हैं।

स्क्वायर फेस शेप को बैलेंस लुक देने के लिए करीना कपूर ने साइड पार्टिशन कर लो पोनी टेल बनाई है। साड़ी पर उनका ये हेयरस्टाइल काफी अच्छा लग रहा है, जिसे आप भी ट्राई कर सकती हैं।

अगर आप चाहती हैं कि आपका फेस थोड़ा पतला लगे तो करीना का ये हेयरस्टाइल ट्राई कर सकती हैं। इसमें एक्ट्रेस ने एक साइड के बालों को क्लिप कर टाई किया हुआ और दूसरे साइड के बाल वेवी किए हैं। इससे फेस काफी बैलेंस लग रहा है।

अगर आपने हैवी मेकअप किया है तो फेस का शो होना जरूरी है। ऐसे में आप फ्रंट हेयर को टाई करके बाकी बालों को खुला छोड़ें। इस हेयरस्टाइल से फेस अच्छे से शो होता है और बाल भी मैनेजेबल रहते हैं।

स्लीक बन हेयरस्टाइल आज कल काफी ट्रेंड में है। अगर आपके पास हेयरस्टाइल बनाने का समय नहीं है तो आप स्लीक बन बना सकती हैं। ये चेहरे को भी अच्छे से शो करेगा और काफी नीट क्लीन लुक मिलेगा।

सुबह की चाय या कॉफी से ज्यादा ऊर्जा दे सकते हैं ये खाद्य पदार्थ

सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग शायद चाय या कॉफी पीते होंगे। ये पेय तरोताजा महसूस करवाते हैं और ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। हालांकि, चाय और कॉफी का नियमित सेवन स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इनके बजाय आप सुबह उठकर इन खाद्य पदार्थों को खान-पान का हिस्सा बना सकते हैं। ये ऊर्जा तो देते ही हैं, साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन भी करते हैं।

केला

केले में प्राकृतिक मिठास और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इस फल में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। ये मांसपेशियों को आराम देने में सहायता कर सकते हैं और पूरे दिन आपको तरोताजा महसूस करा सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य को दुरुस्त करता है, जिससे पेट सुबह ही अच्छी तरह साफ हो जाता है।

एवोकाडो

आप सुबह के नाश्ते में एवोकाडो भी खा सकते हैं, जो एक तरह का सुपरफूड है। सुबह इसे खाने से दिन की पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर शुरुआत मिलती है, जो दिमागी क्षमता को बढ़ाती है। इसके सेवन से आपका पेट देर तक भरा रहेगा और आप ज्यादा खाने से भी बच सकेंगे। इसमें मौजूद स्वस्थ वसा कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है।

ओट्स

ओट्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो सुबह के समय निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इनमें मौजूद घुलनशील फाइबर बीटा-ग्लूकन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों को दूर रखने में मदद मिल सकती है। इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जावान रखने के साथ-साथ इसे आराम देने में सहायता कर सकता है। ओट्स का सेवन करने से भूख भी कम होती है।

बादाम

बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन-श्व और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग को ऊर्जा देने के साथ-साथ तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। इनमें अच्छी वसा भी मौजूद होती है, जो मांसपेशियों को आराम देने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा बादाम में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। इसे खाने से त्वचा और बालों की देखभाल में भी मदद मिलती है।

सेब

सुबह एक सेब खाने से आपको प्राकृतिक रूप से ऊर्जा मिल सकती है। इसमें प्राकृतिक मिठास और फाइबर होता है, जो ऊर्जा बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के साथ-साथ मांसपेशियों को आराम देने में भी सहायक होता है। इसे डाइट में शामिल करने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, वजन घटाने में मदद मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

रोजगार के मोर्चे पर थोड़ी राहत : बेरोजगारी दर में गिरावट, गांवों और महिलाओं ने मारी बाजी

अक्तूबर–दिसंबर 2025 तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। श्रम बल में ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं की भागीदारी में बड़ा उछाल आया है। सांख्यिकी मंत्रालय के नए आंकड़े क्या कह रहे, आइए जानते हैं विस्तार से।

भारतीय अर्थव्यवस्था और जॉब मार्केट के लिए एक राहत भरी खबर है। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में बेरोजगारी दर कम हुई है। अक्तूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही में रोजगार के आंकड़ों ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। इनके अनुसार ग्रामीण भारत और महिला कार्यबल की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि श्रम बाजार अब सुधार की ओर बढ़ रहा है।

ग्रामीण भारतः ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की रफ्तार तेज रही है। यहां बेरोजगारी दर अक्तूबर-दिसंबर 2025 में घटकर चार प्रतिशत रह गई है। इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 4.4 प्रतिशत था। बेरोजगारी दर में गिरावट पुरुष और महिला दोनों वर्गों में रोजगार बढ़ने के कारण आई है।

शहरी भारतः शहरों में भी हालात सुधर रहा है। शहरी बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 6.9 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है। इसमें मुख्य योगदान शहरी पुरुषों का रहा, जिनकी बेरोजगारी दर 6.2 प्रतिशत से गिरकर 5.9 प्रतिशत हो गई है।

महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

इस रिपोर्ट का सबसे उत्साहजनक पहलू श्रम बल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर), जो यह बताती है कि आबादी का कितना हिस्सा काम कर रहा है या काम की तलाश में है, उसमें इजाफा हुआ है।

अक्तूबर-दिसंबर 2025 के दौरान समग्र एलएफपीआर बढ़कर 55.8 प्रतिशत हो गया, जो पिछली तिमाही में 55.1 प्रतिशत था। विशेष रूप से महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक) के लिए यह दर 33.7 प्रतिशत से बढ़कर 34.9 प्रतिशत हो गई है। यह संकेत देता है कि महिलाएं अब बड़ी संख्या में श्रम बल का हिस्सा बन रही हैं।

खेती और स्वरोजगार का आसरा

आंकड़े बताते हैं कि रोजगार सृजन में अब भी पारंपरिक क्षेत्रों का दबदबा कायम हैः

कृषि क्षेत्रः ग्रामीण रोजगार में कृषि क्षेत्र रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। इस तिमाही में नियोजित लोगों में से 58.5 प्रतिशत कृषि से जुड़े थे, जो पिछली तिमाही के 57.7 प्रतिशत से अधिक है।

स्वरोजगारः नौकरी ढूंढने के बजाय लोग अपना काम शुरू करने को तरजीह दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़कर 63.2 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 39.7 प्रतिशत हो गया है।

क्या रोजगार के मार्चे पर हम सही दिशा में बढ़ रहे?

रोजगार का एक अन्य प्रमुख सूचक, श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), जो जुलाई-सितंबर 2025 में 52.2 प्रतिशत था, वह बढ़कर 53.1 प्रतिशत हो गया है। बेरोजगारी दर में गिरावट और डब्ल्यूपीआर में वृद्धि यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। हालांकि, कृषि और स्वरोजगार पर बढ़ती निर्भरता यह भी बताती है कि संगठित क्षेत्र में अभी और अधिक अवसरों की जरूरत है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से बाजार और अर्थव्यवस्था को फायदा कैसे

भारत और अमेरिका ने लंबे समय के इंतजार के बाद व्यापार समझौते की घोषणा की है। उम्मीद है कि इससे कारोबारी रिश्तों में सुधार आएगा क्योंकि अमेरिका आज भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है। विशेषज्ञों और ब्रोकरेज रिपोर्ट बताती हैं समझौते के तहत अमेरिक ने भारतीय सामान पर पारस्परिक टैरिफ को पहले घोषित 25 प्रतिशत की दर की तुलना में घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा 25 प्रतिशत का पैनल्टी टैरिफ भी वापस ले लिया गया है। कुल मिलाकर टैरिफ बोझ जो 50 प्रतिशत था, वह अब घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। मोतीलाल फाइनेंशियल लिमिटेड की रिपोर्ट ने कहा है कि इस समझौते से भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था को कई तरह से फायदा मिलेगा। इक्विटी मार्केट की नजर से देखें तो समझौते होने और हाल ही में भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से भारत की स्थिति काफी मजबूत होती दिख रही है। इससे निर्यात वृद्धि को समर्थन मिलने, डॉलर के मुकाबले रुपये जारी गिरावट को कम करने, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को आकर्षित करने और मीडियम टर्म में करेंसी को स्थिर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

वहीं मूडीज की रिपोर्ट बताती है इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साल 2025 के पहले 11 महीनों में भारत के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका को गया। इसके अलावा, कम शुल्क दर रत्न व आभूषण, कपड़ा और परिधान जैसे श्रम-प्रधान सेक्टर के लिए भी सकारात्मक साबित होगा। मूडीज ने यह भी चेताया कि अगर भारत रूसी तेल से पूरी तरह हटकर अन्य स्रोतों पर निर्भर हो जाता है, तो इससे तेल की आपूर्ति और कड़ी हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके चलते महंगाई पर भी दबाव बढ़ने का खतरा रहेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में सुधार

बजाज ब्रोकिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में सुधार लाएगा। हालांकि इसके पूरी जानकारी आनी बाकी है। जिन सेक्टर को सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है, उनमें टेक्सटाल और वस्त्र जेम्स और ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, लेदर और फुटवियर शामिल हैं। यह समझौता निर्यात पर आधारित एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए अनिंग्स विजबिलिटी भी बढ़ा सकता है। साथ ही आईटी सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल्स में शॉर्ट-टर्म रिकवरी में भी मदद कर सकता है। हालांकि, ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्युमीनियम जैसे सेक्टर्स पर सेक्शन 232 के तहत लगाए गए टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

टेक्सटाइल और परिधान

रिपोर्ट के अनुसार टेक्सटाइल और परिधान सेक्टर की यूएस बाजार पर निर्भरता अधिक है, जिसमें होम टेक्सटाइल, मेड-अप्स और कपड़ों में कम टैरिफ से बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के निर्यातकों के मुकाबले भारत की लैंडेड-प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बेहतर होती है। इससे ऑर्डर अधिक मिलेंगे, पूरी क्षमता का इस्तेमाल और मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। यह सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, इसके कम मार्जिन को देखते हुए, मामूली टैरिफ कटौती भी अमेरकी रिटेलर्स के सोर्सिंग के फैसलों पर काफी असर डाल सकती है।

ऑटो एंसिलरीज

भारतीय ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूएस ओईएम और टियर -1 सप्लायर्स को फोर्जिंग, कास्टिंग, एक्सल, टायर वगैरह प्रिसिजन कंपोनेंट एक्सपोर्ट करते हैं। कम टैरिफ से मेक्सिको और चीन के सप्लायर्स के मुकाबले मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे भारत से सोर्सिंग बढ़ सकती है।

फार्मास्यूटिकल्स

यह समझौता फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि यूएस भारतीय जेनेरिक और APIs के लिए सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। कम टैरिफ से चीन और दूसरे सप्लायर्स के मुकाबले मूल्य प्रतिस्पर्धा बेहतर होती है, बहुत ज्यादा प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में मार्जिन को सपोर्ट मिलता है, और चल रहे आपूर्ती श्रृंखला डाइवर्सिफिकेशन के बीच भारत से सोर्सिंग को बढ़ावा मिलता है।

केमिकल्स

यूएस में बाजार में अधिक मांग वाले विशेष केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स के निर्यातकों को बेहतर ट्रेड इकोनॉमिक्स और चीन से दूर लगातार डाइवर्सिफिकेशन से फायदा होगा। टैरिफ में राहत से बेहतर मूल्य, अधिक वॉल्यूम और मजबूत कस्टमर रिलेशन मिल सकते हैं।

जेम्स एंड ज्वेलरी

उद्योग का कहना है रत्न और आभूषण क्षेत्र पहले की टैरिफ व्यवस्था से सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक था, क्योंकि 50 प्रतिशत शुल्क का सबसे अधिक बोझ इसी क्षेत्र पर पड़ा था। रत्न और आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को इस फैसले से स्पष्ट रूप से लाभ होगा और यह कदम न केवल निर्यात को बढ़ावा देगा बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद करेगा।

काम ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत होना भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक बड़ी राहत है। अमेरिका भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी का एक बड़ा उपभोक्ता बाजार रहा है और टरिफ के असर की वजह से इसके सेंटिमेंट पर बुरा असर पड़ा। इस समझौते से भारतीय ज्वेलरी बनाने वालों और निर्यातकों का अमेरिका बाजार में भरोसा फिर से बढ़ेगा।

टैरिफ कटौती से विनिर्माण, रोजगार और निर्यात बढ़ेगा

चैंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (सीएएमआईटी) के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल कहते हैं कि 18 प्रतिशत टैरिफ कटौती न केवल पहले से मौजूदा लगात संबंधी असमानताओं को दूर करती है, बल्कि विनिर्माण को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और निर्यात विविधीकरण पर केंद्र सरकार के दीर्घकालिक फोकस के अनुरूप भी है। अमेरिकी बाजार तक बेहतर और निष्पक्ष पहुंच मिलने से भारतीय निर्यातक उच्च मूल्य वाले उत्पादों की मांग का बेहतर लाभ उठा सकेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उद्योग की वृद्धि और रोजगार पर पड़ेगा। विश्व बाजारों में से एक में लागत कम होगी और भारतीय निर्यात बढ़ेगा, जो मेक इन इंडिया और निर्यात आधारित विकास को मजबूत करेगा।

वे कहते हैं, जहां एक ओर टैरिफ में कमी से भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर अमेरिका से शून्य शुल्क पर आयात होने वाले उत्पाद घरेलू विनिर्माण उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों मुख्य हैं।

इनक्रेड वेल्थ के सीईओ नीतिन राव ने कहा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा हो गई है और कुछ दिनों में इसमें हस्ताक्षर भी हो जाएंगी, लेकिन देखना यह होगा कि यह आगे कैसे बढ़ता है। भारत साफ तौर पर अपने निर्यात बाजार के लिए और एक बड़े फाइनेंशियल पार्टनर के साथ जुड़ने से होने वाले फायदों के लिए अमेरिका को एक स्टेबल पार्टनर के तौर पर चाहता था। हमारा मानना है कि इसके नतीजे में अलग-अलग तरह से फंड फ्लो बेहतर हो सकता है, क्योंकि दो बड़े देशों के बीच तालमेल का मजबूत संदेश अमेरिका के वित्तीय प्रणाली में जाएगा, जिससे फिर से एक अच्छा बिजनेस माहौल बनेगा। हालांकि मार्केट वैल्यूएशन को डिस्काउंट करते हैं और उनके पूरी तरह से आकर्षित बनने में अभी कुछ समय बाकी है, हमारा मानना है कि यह डील मार्केट के लिए एक फ्लोर बना सकती है, जहां से ग्रोथ और वैल्यूएशन भविष्य की मार्केट दिशा तय करेंगे।

ईरान मुद्दे पर ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू, परमाणु वार्ता पर रखेंगे पक्ष, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है। हाल ही में ओमान में दोनों देशों के बीच पर परमाणु समझौते पर पहले दौर पर बैठक बेनतीजा रही। हालांकि आने वाले दिनों में फिर से वार्ता की जाएगी। इस बीच इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। जिसकी जानकारी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने दी।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस्राइली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा नीति और नियमों में ढील (डीरेगुलेशन) पर चर्चा होने की संभावना है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान लेविट ने यह भी घोषणा की है कि राष्ट्रपति ट्रंप साल 2009 में ओबामा प्रशासन के दौरान किए गए 'एंडेंजर्मेंट फाइंडिंग' (खतरा निर्धारण) को रद्द करने जा रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति इस्राइली पीएम नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस सप्ताह का बाकी समय ऊर्जा और डीरिगुलेशन पर केंद्रित रहेगा। गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप, प्रशासक ली जेल्डिन के साथ मिलकर 2009 की ओबामा-कालीन एंडेंजर्मेंट फाइंडिंग को औपचारिक रूप से रद्द करेंगे। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी डीरेगुलेशन कार्रवाई होगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों को 1.3 ट्रिलियन डॉलर के कठोर नियमों से राहत मिलेगी।'

ट्रंप-एपस्टीन को लेकर क्या बोला व्हाइट हाउस?

इसी के साथ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, 'राष्ट्रपति हमेशा एक जैसे रहे हैं और उन्होंने जेफरी एपस्टीन को मार-ए-लागो में अपने क्लब से निकाल दिया था, क्योंकि जेफरी एपस्टीन एक घिनौना इंसान था। इन फाइलों में जिन दूसरे लोगों के नाम हैं, उनसे अलग, राष्ट्रपति ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए और साल तक इस बारे में ईमानदार और पारदर्शी रहे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने जो भी कहा है, वह हमेशा सच रहा है। जेफरी एपस्टीन और उसके घिनौने, घिनौने अपराधों से जुड़े 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज का जारी होना दिखाता है कि इस राष्ट्रपति और प्रशासन ने इन फाइलों को सामने लाने में कितनी पारदर्शिता दिखाई है।'

ईरान मुद्दे पर ट्रंप से बात करेंगे नेतन्याहू

मंगलवार को वॉशिंगटन रवाना होते समय नेतन्याहू ने कहा कि वे ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ अमेरिका की परमाणु वार्ता पर अपना रुख रखेंगे। 'द टाइम्स ऑफ इस्राइल' के अनुसार उड़ान भरने से पहले नेतन्याहू ने मीडिया से कहा, 'मैं राष्ट्रपति के सामने वार्ता को लेकर अपने सिद्धांतों और दृष्टिकोण को पेश करूंगा।' उन्होंने आगे कहा कि ये सिद्धांत न सिर्फ इस्राइल के लिए बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए अहम हैं, जो शांति और सुरक्षा चाहता है।

जलवायु नीति को बड़ा झटका

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन गुरुवार को उस वैज्ञानिक निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द करने जा रहा है, जिसके आधार पर अमेरिका में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का अधिकार सरकार को मिला था। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने पिछले साल 2009 की एंडेंजर्मेंट फाइंडिंग को पलटने का प्रस्ताव रखा था, जिसे जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सहित छह ग्रीनहाउस गैसें मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा हैं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। यह निर्णय 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मैसाचुसेट्स बनाम ईपीए, पर आधारित था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि ग्रीनहाउस गैसें स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत प्रदूषक हैं और ईपीए को यह निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था कि क्या वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा पैदा करती हैं।

कनाडा के स्कूल में गोलीबारी, हमलावर समेत दस की मौत, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां एक स्कूल में हुई गोलीबारी में हमलावर समेत दस लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। यह जानकारी मंगलवार को कनाडाई पुलिस ने दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) के अनुसार, संदिग्ध हमलावर मृत पाया गया है। पुलिस का मानना है कि उसने खुद को गोली मारी। हालांकि, अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस घटना में कोई दूसरा संदिग्ध भी शामिल था।

बता दें कि गोलीबारी टम्बलर रिज नामक छोटे शहर में हुई, जिसकी आबादी लगभग 2,400 लोग है। पुलिस ने लोगों से घर के अंदर रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। आसपास के क्षेत्रों से अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजे गए हैं।

स्कूलों में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

पीस रिवर साउथ स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने बताया कि टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल और टम्बलर रिज एलीमेंट्री स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। बता दें कि टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 7 से 12 तक लगभग 175 छात्र पढ़ते हैं।

भारी सुरक्षा और मेडिकल सहायता

पीस रिवर साउथ के विधायक लैरी न्यूफेल्ड ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस और एंबुलेंस जैसी अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। उन्होंने सुरक्षा कारणों से ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार किया। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपील की है कि जो लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कृपया घर लौट जाएं और पुलिस को काम करने दें। कैनेडियन माउंटेड पुलिस इस खूबसूरत शहर को फिर से सुरक्षित बनाएगी।

ट्रंप अपनी ही पार्टी के सांसदों से घिरे, चुनाव में धांधली की जांच में दखल पर कटघरे में राष्ट्रपति

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिशों की जांच को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन सांसदों ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान कुछ मौजूदा सांसदों के फोन रिकॉर्ड हासिल करने के लिए हद से ज्यादा दखल देने वाले तरीके अपनाए गए। मंगलवार को सीनेट की एक सुनवाई में रिपब्लिकन नेताओं ने बड़ी टेलीकॉम कंपनियों से सवाल किए कि उन्होंने अभियोजकों को सांसदों के फोन रिकॉर्ड क्यों दिए? मामले में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अगर ऐसा किसी डेमोक्रेट सांसद के साथ होता, तो यह दुनिया भर की सुर्खियां बनता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ जो हुआ, मैं उसका हकदार था। जांच के दौरान अभियोजकों ने उन सांसदों के

कॉल रिकॉर्ड लिए थे, जिनसे ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को संपर्क किया था। उस दिन कांग्रेस में जो बाइडन की जीत की पुष्टि हो रही थी। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि रिकॉर्ड में सिर्फ यह जानकारी थी कि कॉल कब हुई और कितनी देर चली। बातचीत की सामग्री रिकॉर्ड नहीं की गई थी।

20 रिपब्लिकन सांसदों के रिकॉर्ड मांगे गए

सीनेट न्यायिक समिति के अध्यक्ष चक ग्रासले ने बताया कि कुल मिलाकर 20 मौजूदा या पूर्व रिपब्लिकन सांसदों के फोन रिकॉर्ड के लिए समन जारी किए गए थे। वहीं डेमोक्रेट सांसदों ने रिपब्लिकन नेताओं की नाराजगी को गलत बताया। उनका कहना है कि 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल भवन पर हमला किया था, जो लोकतंत्र पर बड़ा हमला था। ऐसे में यह जांच जरूरी था। डेमोक्रेट सीनेटर शेल्डन व्हाइटहाउस ने कहा कि न्याय विभाग की जांच, कैपिटल पर हुए हमले से ज्यादा गंभीर नहीं थी। वहीं पूर्व संघीय अभियोजक माइकल रोमानो ने भी कहा कि फोन कॉल के रिकॉर्ड जुटाना किसी भी आपराधिक जांच में सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से रिकॉर्ड जुटाए जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ।

कंपनियों ने कहा- हमने कानून का पालन किया

टेलीकॉम कंपनियों के वकीलों ने सुनवाई में कहा कि उन्होंने सिर्फ कानून का पालन किया। वेरिजोन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी क्रिस मिलर ने कहा कि हमें कानून के तहत यह जानकारी देने के लिए बाध्य किया गया था। हम वैध कोर्ट ऑर्डर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी बताया कि समन में यह नहीं बताया गया था कि ये नंबर सांसदों के हैं। साथ ही, कोर्ट के आदेश के कारण कंपनी संबंधित नेताओं को पहले से सूचना भी नहीं दे सकती थी।

अन्य मोबाइल कंपनियों के बयान भी मिले जुले

इसके साथ ही टी-मोबाइल और एटीएंडटी ने भी इसी तरह का बयान दिया। एटीएंडटी के अधिकारी डेविड मैकएटी ने कहा कि एक मामले में उन्होंने विशेष कानूनी सुरक्षा (संविधान की 'स्पीच या डिबेट' क्लॉज) को लेकर सवाल उठाया, लेकिन बाद में अभियोजकों ने वह समन वापस ले लिया। वेरिजोन ने कहा है कि अब से सांसदों से जुड़ी जानकारी देने से पहले कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। जहां संभव होगा, संबंधित सांसद को भी जानकारी दी जाएगी और गोपनीयता आदेश को चुनौती दी जाएगी।

'गृह जिले में पोस्टिंग है तो ट्रांसफर करें...',

चुनावी राज्यों में अफसरों की तैनाती को लेकर ईसी का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकतंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक बार फिर कमर कस ली है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोग ने मंगलवार को इन राज्यों के मुख्य सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए।

चुनाव से जुड़े सभी अफसरों को उनके गृह जिले में या जहां वे पिछले चार साल में तीन साल पूरे कर चुके हैं या 31 मई तक कर लेंगे, वहां से तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं। पुडुचेरी के मामले में यह समयसीमा 30 जून तक है। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि कोई भी अफसर अपनी पुरानी पोस्टिंग के कारण पक्षपात का आरोप न झेल सके।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी या पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के स्तर के अफसरों को उसी विधानसभा क्षेत्र या जिले में नहीं रहने दिया जाएगा या नहीं पोस्ट किया जाएगा, जहां वे पिछली विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी उपचुनाव में तैनात थे। यह नियम सुनिश्चित करेगा कि पुराने रिश्ते या प्रभाव से चुनाव प्रभावित न हों।

घरेलू जिले में पोस्टिंग पर पूरी रोक

आयोग के निर्देशों के मुताबिक, चुनाव से सीधे जुड़े अफसरों को उनके गृह जिले में बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। साथ ही, अगर कोई अफसर वर्तमान जिले में पिछले चार साल में तीन साल या उससे ज्यादा समय बिता चुका है या 31 मई (पुडुचेरी के लिए 30 जून) तक बिता लेगा, तो उसे भी ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिवों को इन तबादलों को जल्द पूरा करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है।

पटना में पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई! 20 मामलों में वांछित कुख्यात 'सूर्या' मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

पटना, एजेंसी। बिहार पुलिस ने बुधवार तड़के एक साहसिक ऑपरेशन में पटना के आलमगंज इलाके से कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। सूर्या पर लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कम से कम 20 संगीन मामले दर्ज हैं। पटना (पूर्व) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परिचय कुमार के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सूर्या आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट इलाके में किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (STF) की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। उन्होंने कहा, "सूचना मिली थी कि शस्त्र अधिनियम, लूट, डकैती और रंगदारी से जुड़े करीब 20 मामलों में वांछित राजीव कुमार गायघाट स्थित एक स्थान पर छिपा हुआ है। इसके बाद जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम गठित कर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।"

स्कूल से सिनेमा हॉल तक गूंजेगा वंदे मातरम, गृह मंत्रालय ने जारी किया नया नेशनल प्रोटोकॉल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को वंदे मातरम के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाया जाना चाहिए और इसके बजने के दौरान सभी को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 के दशक में लिखा था और 1950 में अपनाया गया था। अब पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक पुरस्कार समारोहों और राष्ट्रपति की उपस्थिति में आयोजित होने वाले सभी अन्य कार्यक्रमों में उनके आगमन और प्रस्थान के दौरान राष्ट्रगीत बजाना अनिवार्य होगा।

सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, हालांकि इस दौरान खड़े होना अनिवार्य नहीं है। और इसके सभी छह श्लोक बजाए जाएंगे, जिनमें वे चार श्लोक भी शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस ने 1937 में हटा दिया था। पहले, जन गण मन राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय प्रोटोकॉल परिभाषित नहीं था। इस निर्णय का उद्देश्य राष्ट्रगीत के सम्मानपूर्वक पालन को औपचारिक रूप देना और आधिकारिक समारोहों, विद्यालयों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह कदम संसद में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक महत्व पर हुई बहसों के बाद राष्ट्रीय प्रतीकों को लोकप्रिय बनाने और उन पर जोर देने के निरंतर प्रयासों को भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक साल तक चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है और यह मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ताधारी सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के बीच विवाद का मुख्य कारण भी बन गया था। इस निर्देश और उन चार श्लोकों को शामिल करने से विवाद खड़ा होने की संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले साल इस मुद्दे पर सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी।

यह घटना तब हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूर्ववर्ती जवाहरलाल नेहरू पर मुहम्मद अली जिन्ना का अनुसरण करते हुए इस गीत का विरोध करने का आरोप लगाया क्योंकि इससे मुसलमानों को ठेस पहुंच सकती थी। इसके बाद भाजपा ने अपने दावे के समर्थन में नेहरू के पत्र साझा किए और गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में हुई 'बहस' के बाद यह विवाद कटुतापूर्ण हो गया।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने राघव चड्ढा को कहा 'हैंडसम', परिणीति ने दिया जवाब, वायरल हुआ एक्ट्रेस का रिएक्शन

हाल ही में जब एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को 'हैंडसम' कहा, तब परिणीति चोपड़ा ने मजेदार रिएक्शन दिया। जानिए उनका रिएक्शन, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है।

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की थी। दोनों सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक इंफ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर रील शेयर कर राघव चड्ढा को हैंडसम कहा, जिस पर परिणीति का रिएक्शन चर्चाओं का विषय बन गया है।

दरअसल, पियूष त्रिपाठी नाम के एक इंफ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें वह अपने पार्टनर के साथ एयरपोर्ट पर सस्ते खाने का मजा लेते नजर आए। दोनों यह देखकर हैरान थे कि जहां आमतौर पर एयरपोर्ट पर खाना बहुत महंगा होता है, वहीं यहां चाय सिर्फ 10 रुपये और समोसा 20 रुपये में मिल रहा था। वीडियो में इंफ्लुएंसर ने इस पहल का श्रेय राघव चड्ढा को दिया।

राघव और परिणीति ने किया कमेंट

इसके बाद जब उसने अपनी पार्टनर से पूछा, 'राघव चड्ढा कैसे लगते हैं?' तो उसने हंसते हुए जवाब दिया- 'हैंडसम।' यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद कमेंट सेक्शन में खुद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कमेंट में राघव ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'हाहा, उम्मीद है समोसा अच्छा लगा होगा!' इसके बाद इंफ्लुएंसर ने परिणीति को टैग करते हुए लिखा - 'मैम अब तो आप भी कुछ कह दो, सर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है इधर।' इस पर परिणीति ने मजेदार रिएक्शन देते हुए लिखा, 'मैं पूरी तरह सहमत हूं।' साथ में उन्होंने आंख और नर्वस हंसी वाले इमोजी भी लगाए।

इस सीरीज में नजर आएंगी परिणीति

वर्कफ्रंट की बात करें तो परिणीति चोपड़ा आखिरी बार इम्तियाज अली की 2024 की नेटफ्लिक्स फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं। जल्द ही वह वेब सीरीज 'तलाशः ए मदर्स सर्च' में दिखाई देंगी।

सेलिना जेटली के भाई विक्रांत के डिटेंशन केस में आया नया अपडेट, इस तारीख को होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

सेलिना जेटली के भाई विक्रांत जेटली की हिरासत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्रालय द्वारा कानूनी सहायता वापस लेने पर सवाल उठाया है।

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली के भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली का मामला काफी समय से चर्चा में है। विक्रांत जेटली भारतीय सेना में स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। वहीं आज हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपनी अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

विक्रांत जेटली केस में ताजा जानकारी

मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय के वकील से कहा कि वे MEA से संपर्क करें ताकि विक्रांत जेटली कोर्ट से बात कर सकें। कोर्ट ने MEA से सवाल भी किया कि उन्होंने पहले UAE की एक कानूनी फर्म को विक्रांत का केस लड़ने के लिए अधिकृत किया था, लेकिन बाद में उनकी पत्नी चारुल के कारण इसे वापस क्यों ले लिया? कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी मदद को पारिवारिक विवादों पर निर्भर नहीं किया जा सकता। अब हाई कोर्ट ने MEA को निर्देश दिया है कि UAE की एक फर्म को विक्रांत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए, ताकि उन्हें ठीक से कानूनी सहायता मिल सके। कोर्ट ने उनकी सुरक्षा और संपर्क की भी बात की।

क्या हुआ है पूरा मामला?

सितंबर 2024 में दुबई (UAE) में विक्रांत जेटली को अचानक हिरासत में ले लिया गया। UAE की तरफ से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताया गया, लेकिन अब तक परिवार को उनके खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप या केस की जानकारी नहीं दी गई है। वे पिछले 17-18 महीनों से हिरासत में हैं (अबू धाबी के अल वथ्बा डिटेंशन सेंटर में)। परिवार का कहना है कि यह हिरासत मनमानी और गैरकानूनी है और उनसे लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं हो पाया।

अगली सुनवाई कब?

सेलिना के भाई विक्रांत जेटली केस के मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की गई है। सेलिना जेटली ने इसे एक बड़ी उम्मीद की किरण बताया है और कहा है कि वे अपने भाई (जो देश के लिए सैनिक रहे) को वापस लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगी। सेलिना ने अपने भाई की रिहाई के लिए काफी संघर्ष किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद मांगी है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें विदेश मंत्रालय (MEA) से कानूनी मदद मांगी गई।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस : वर्ल्डवाइड 500 करोड़ के करीब सनी देओल की फिल्म, रविवार को लगाया कमाई का अंबार

बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार 17 दिन पूरे कर लिए हैं। फिल्म ने इन 17 दिनों में वर्ल्डवाइड 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है। वहीं, फिल्म भारत में 350 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंच चुकी है। सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर वॉर वेस्ड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रखा है। फिल्म अब अपने 500 करोड़ रुपये के कलेक्शन के करीब पहुंचती जा रही है। अभी भी फिल्म के पास इस शुक्रवार तक कमाने का मौका है। क्योंकि इस शुक्रवार से बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्में रिलीज होने जा रही है।

बॉर्डर 2 ने 17 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार 458।16 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। फिल्म अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही है। फिल्म भारत में 350 करोड़ रुपये की ओर भी बढ़ती नजर आ रही है। फिल्म ने 14 दिनों में 323। 89 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 17वें दिन रविवार को 6।90 करोड़ रुपये कमाए हैं। रविवार के दिन बॉर्डर 2 का हिंदी पट्टी में ऑक्यूपेंसी रेट 21।17 फीसदी दर्ज हुआ है। बता दें, बॉर्डर 2 ने भारत में 375।12 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है और भारत में सबसे कमाऊ 50 फिल्मों की लिस्ट में वह 30वें नंबर पर है। इसमें उसने धूम 3, कांतारा, टाइगर 3, देवरा पार्ट 1, आदिपुरुष, कूली और साहो जैसे बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

बॉर्डर 2 की सफलता के बीच बॉर्डर 3 का भी ऐलान किया जा चुका है। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार और निधि दत्ता ने बॉर्डर 3 की गुडन्यूज फैंस को दी थी और अब फिल्म की रिलीज डेट का इंतजार है। वहीं, बॉर्डर 2 की बात करें तो इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह लीड रोल में हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना का भी कैमियो दिखाया जा रहा है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com